ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

online- jwalaexpress.com

वर्ष - 05, अंक -23 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 05 फरवरी से 11 फरवरी 2026 (प्रत्येक गुरूवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के तहत जशपुर को मिली पर्यटन विकास की बड़ी सौगात

ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा मयाली : मुख्यमंत्री साय

होम-स्टे, रिसोर्ट, पाथवे, लैंडस्केपिंग सहित आधुनिक पर्यटक सुविधाओं का होगा विकास

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने भारत सरकार की स्वदेश दर्शन योजना 2.0 की उप-योजना सीबीडीडी के अंतर्गत स्वीकृत मयाली-बगीचा विकास परियोजना का मयाली नेचर कैंप में विधिवत भूमिपूजन किया। लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से क्रियान्वित इस परियोजना के तहत मयाली, विश्व प्रसिद्ध मधेश्वर पर्वत (विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग) तथा बगीचा स्थित कैलाश गुफा क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

यह परियोजना क्षेत्र की प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवं जनजातीय विरासत के संरक्षण के साथ-साथ समुदाय आधारित पर्यटन को सशक्त बनाएगी। इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और जशपुर जिले को एक प्रमुख पर्यटन गंतव्य के रूप में नई पहचान मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्रवासियों को बधाई देते हुए कहा कि मयाली-बगीचा विकास परियोजना जशपुर जिले के पर्यटन विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल है। आज मयाली के विकास की मजबूत नींव रखी गई है। मयाली अब पर्यटन मानचित्र पर तेजी से उभर रहा है और आने वाले समय में यह एक वैश्विक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मयाली की पहचान सदियों से मधेश्वर महादेव से जुड़ी रही है, जिसे विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। इस विकास परियोजना के माध्यम से मधेश्वर पर्वत के धार्मिक एवं पर्यटन महत्व को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। परियोजना के अंतर्गत मयाली डेम के समीप पर्यटक रिसोर्ट एवं स्किल डेवलपमेंट सेंटर का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मयाली को एक समग्र इको-टूरिज्म और एडवेंचर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 10 रुपये की टिकट कटाकर मयाली नेचर कैंप में लिया एडवेंचर स्पोर्ट्स का आनंद

पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स से युवाओं को मिल रहे रोजगार के अवसर - मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अलग अंदाज़ में नजर आए और उन्होंने 10 रूपए का टिकट कटाकर जिले के लोकप्रिय पर्यटन स्थल मयाली नेचर कैंप में साहसिक खेल गतिविधियों का आनंद लिया और कई नए एडवेंचर स्पोर्ट्स की औपचारिक शुरुआत भी की।

मुख्यमंत्री ने प्रवेश शुल्क अदा कर नेचर कैंप में प्रवेश करते हुए आम नागरिकों को नियमों के पालन और समानता का एक सशक्त संदेश दिया। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या साय, विधायक श्रीमती गोमती साय, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, पर्यटन विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव, छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री विवेक आचार्य सहित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी-कर्मचारी एवं खेल प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस दौरान नेचर कैंप में विकसित अधोसंरचनाओं, सुरक्षा व्यवस्था, पर्यटकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं तथा स्थानीय युवाओं को स्वरोजगार से जोडने के पहल की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रकृति-आधारित पर्यटन एवं साहसिक गतिविधियां न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित करती हैं।

मुख्यमंत्री ने 4 नए एडवेंचर स्पोर्ट्स का किया शुभारंभ

मुख्यमंत्री साय ने मयाली नेचर कैंप में संचालित स्पोर्ट्स मोटर बाइक (एटीवी) को स्वयं चलाकर साहसिक पर्यटन का आनंद लिया। इसके साथ ही उन्होंने बंदूक से सटीक निशाना साधते हुए बैलून शूटिंग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने आर्चरी शूटिंग में तीर चलाकर निशाना साधा और इस खेल की भी शुरुआत की। साथ ही उन्होंने माउंटेन साइक्लिंग का शुभारंभ करते हुए स्वयं साइकिल चलाकर स्वस्थ जीवनशैली का संदेश दिया। नेचर कैंप में वॉल क्लाइंबिंग बोर्ड का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया।

थक गए, चले गए : पीएम मोदी का विपक्ष के वॉकआउट पर तंज, बोले-

कांग्रेस सरकारों के पास न विजन था, न इच्छाशक्ति

कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के कामकाज पर पीएम मोदी का कटाक्ष

नई दिल्ली (ए)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के जवाब में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खरगे की उम्र को लेकर चुटकी ली। उन्होंने कहा आदरणीय खरगे जी की उम्र को देखते हुए, अगर वे बैठकर भी नारे लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। पीछे कई युवा नेता मौजूद हैं।

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी तीखा हमला करते हुए कहा जो लोग थक गए, वे चले गए। लेकिन इनसे सवाल करना जरूरी है कि देश की हालत ऐसी क्यों थी कि कोई भी देश हमसे समझौता करने नहीं आया। आपने कोशिश की होगी, लेकिन कोई आपके साथ काम करने को तैयार नहीं था। कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्रियों के कामकाज पर टिप्पणी करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अगर आप लाल किले से कांग्रेस के प्रधानमंत्रियों के भाषणों का विश्लेषण करें तो साफ दिखेगा कि न उनकी कोई स्पष्ट सोच थी, न विजन और न ही इच्छा शक्ति।

इसका नतीजा देश को भुगतना पड़ा। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं। सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उन्हें सरकार चलाने का अवसर मिला है। लेकिन उनकी पहचान क्या बनी है। आज डील की चर्चा होती है तो गर्व से कहते हैं, तब बोफोर्स डील याद आता था। उन्होंने सिर्फ जेब भरने का काम किया। नागरिकों की जिंदगी में बदलाव उनकी प्राथमिकता नहीं थी। उन्होंने कहा कि एक हमारे माननीय सदस्य यहां बैठे बोल रहे थे।

संसद भवन परिसर में राहुल गांधी द्वारा केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहे जाने पर पीएम मोदी ने नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को शातिर दिमाग युवराज बता दिया।

प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल को शातिर दिमाग युवराज बताया, कहा- पार्टी बदल दी तो गद्दार हो गए?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच की घटना का भी जिक्र किया।

इस दौरान पीएम मोदी ने राहुल के गद्दार वाले बयान पर निशाना साधते हुए उन्हें शातिर दिमाग युवराज बता दिया। पीएम मोदी ने कहा, कल जो घटना घटी, इसी सदन के सांसद कांग्रेस के शातिर दिमाग युवराज ने उन्हें गद्दार कह दिया। अहंकार सातवें आसमान पर पहुंच चुका है उनका। कांग्रेस को छोड़कर कितने लोग निकले हैं। कई लोग दूसरे देशों में गए हैं। और किसी को तो उन्होंने गद्दार नहीं कहा है। लेकिन कल उन्होंने सांसद को गद्दार कहा क्योंकि वो सिख थे। उनके अंदर सिखों के लिए जो नफरत भरी है, यह उसका ही उदाहरण था।

संक्षिप्त समाचार

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर तेजी: पीयूष

नईदिल्ली। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका मिड-मार्च तक एक औपचारिक, कानूनी व्यापार समझौते के पहले चरण पर साइन करने की योजना बना रहे हैं। इससे पहले एक संयुक्त बयान पर वर्चुअल सिग्नेचर किए जाएंगे, जिसके अगले चार से पांच दिनों में हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। गोयल ने संवाददाताओं से कहा, संयुक्त बयान के आधार पर एक औपचारिक समझौते का मसौदा तैयार किया जाएगा, जिसे अंतिम रूप देने में एक महीने या डेढ़ महीने का समय लग सकता है।

एआई भारतजेन तैयार, 22 भाषाओं में करेगा काम

नईदिल्ली। भारत सरकार की खास योजना भारतजेन अब अपने अंतिम चरण में है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि इस महीने के अंत तक यह एआई सिस्टम भारत की सभी 22 आधिकारिक भाषाओं में लिखने में सक्षम हो जाएगा। खास बात यह है कि इनमें से 15 भाषाओं में लिखने के साथ-साथ बोलने और तस्वीरों को पहचानने की सुविधा विकसित कर ली गई है। गौरतलब है कि भारतजेन को अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया था। यह सरकार की एक प्रमुख परियोजना है, जिसके तहत भारत के लिए एक संप्रभु AI मॉडल विकसित किया जा रहा है।

लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार

नईदिल्ली। वैश्विक शेयर बाजारों में कमजोरी के रुझान के बीच, बेंचमार्क सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी गुरुवार को तीन दिन की तेजी को तोड़ते हुए गिरावट के साथ बंद हुए। मंदी के साथ कारोबार शुरू करने के बाद, 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 503.76 अंक या 0.60 प्रतिशत और गिरकर 83,313.93 पर बंद हुआ। दिन के दौरान, यह 666.07 अंक या 0.79 प्रतिशत गिरकर 83,151.62 पर पहुंच गया। 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 133.20 अंक या 0.52 प्रतिशत गिरकर 25,642.80 पर बंद हुआ।

नोएडा इंजीनियर मौत मामले से सबक

यमुना-हिंडन के किनारे खुलेंगी छह जल पुलिस चौकियां

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर-150 स्थित बेसमेंट में गिरकर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद जिले में जल सुरक्षा और जन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में पुलिस कमिश्नरेट ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर द्वारा जिले में छह जल पुलिस चौकियों की स्थापना की योजना तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य यमुना और हिंडन नदी, नहरों, घाटों एवं जल पर्यटन स्थलों पर आने वाले श्रद्धालुओं और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

साथ ही आपदा की स्थिति में त्वरित बचाव और राहत कार्यों को प्रभावी बनाना है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार श्रावण मास की कांवड़ यात्रा, छठ पूजा, दुर्गा पूजा समेत विभिन्न धार्मिक आयोजनों के दौरान घाटों पर भारी भीड़ उमड़ती है। ऐसे में जल दुर्घटनाओं, अवैध गतिविधियों और कानून-व्यवस्था से जुड़ी चुनौतियों की आशंका बढ़ जाती है।

इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जिले में रणनीतिक स्थानों पर जल पुलिस चौकियों की स्थापना प्रस्तावित की गई है। योजना के तहत नोएडा जोन में थाना सेक्टर-126 क्षेत्र के अंतर्गत ओखला बैराज की पूर्व दिशा में कालिंदी कुंज यमुना पुल के नीचे एक जल पुलिस चौकी स्थापित की जाएगी।

सेंट्रल नोएडा जोन में थाना इकोटेक-3 क्षेत्र के कुलेसरा इलाके में हिंडन नदी के किनारे चौकी प्रस्तावित है।

आपात स्थिति में त्वरित बचाव कार्य होगा करना

जल पुलिस चौकियों का मुख्य दायित्व घाटों पर शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखना, भीड़ प्रबंधन, बैरिकेडिंग, नावों की निर्धारित क्षमता के अनुसार संचालन सुनिश्चित करना और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित बचाव कार्य करना होगा। इसके लिए स्थानीय नाविकों, गोताखोरों और आपदा मित्रों के साथ समन्वय स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जल पुलिस चौकी को आधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा।

बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता, 54 लाख रुपए घोषित था इनाम

हथियारों के साथ 12 माओवादियों ने किया सरेंडर

बीजापुर। जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियद नेल्लानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक डीवीसीएम सहित कुल 12 सशस्त्र माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है।

आत्मसमर्पण करने वालों में 08 महिला माओवादी और 04 पुरुष माओवादी शामिल हैं। इन सभी माओवादियों पर कुल 54 लाख रुपये का इनाम घोषित था। आत्मसमर्पण के दौरान माओवादियों ने अपने साथ एक AK-47 और दो स्क्र राइफल भी पुलिस को सौंपे।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले सभी 12 माओवादी फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट, आगजनी सहित कई गंभीर नक्सली घटनाओं में शामिल रहे हैं।

यह आत्मसमर्पण बस्तर आईजी पी. सुंदरराज, सीआरपीएफ डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉ. जितेंद्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूलेण्डन यार्क, डीएसपी शरद जायसवाल, उप पुलिस अधीक्षक विनीत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को शासन की पुनर्वास नीति के तहत अधिकारियों ने प्रत्येक को 50-50 हजार रुपये की नगद सहायता राशि प्रदान की। पुलिस ने बताया कि वर्ष 2026 में अब तक कुल 888 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है, वहीं 1163 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है।

नक्सलियों ने छुपा रखा था भारी मात्रा में ब्लास्ट का सामान, पुलिस ने किया जब्त

छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के 'हथियार निर्माण' के नेटवर्क पर अब तक की सबसे बड़ी चोट की है. डीआरजीऔर जिला पुलिस बल ने अबूझमाड़ के अंदरूनी इलाके में छापेमारी कर नक्सलियों द्वारा छिपाया गया हथियारों का एक विशाल डंप बरामद किया है. इस कार्रवाई को माओवाद के ताबूत में आखिरी कील माना जा रहा है.

भारत में अचानक डाउन हुआ एक्स, दिल्ली-मुंबई समेत कई शहरों में सर्विस ठप, यूजर्स परेशान

नई दिल्ली (ए)। गुरुवार, 5 फरवरी को भारत में लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) शाम 4 बजे अचानक डाउन हो गया।

डाउन रिपोर्ट्स पर नजर रखने वाली वेबसाइट डाउन डिटेक्टर के मुताबिक, एक्स वेबसाइट यूजर्स इस समस्या से सबसे ज्यादा परेशान हैं, वहीं कुछ यूजर्स को ये दिक्कतें एप में आ रही हैं। डाउन डिटेक्टर के अनुसार, लगभग 64 फीसदी यूजर्स ने वेबसाइट में समस्या रिपोर्ट की है, जबकि 23% यूजर्स ने एप में परेशानी की बात कही है। वहीं, 13% लोगों का कहना है कि उन्हें लॉगइन या लॉगआउट में दिक्कतें आ रही हैं।

बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष अनुराग को सुको से राहत

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई से जुड़े एक मामले में अपने जनवरी 2017 के आदेश में संशोधन करते हुए पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर को बड़ी राहत दी है। शीर्ष अदालत ने कहा है कि अनुराग ठाकुर अब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के मामलों में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुपातिकता के सिद्धांत को लागू करते हुए अपने पुराने आदेश में बदलाव किया। बता दें कि, जनवरी 2017 में अदालत ने अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई के कामकाज से सीज एंड डिसिस्ट यानी पूरी तरह दूर रहने का निर्देश दिया था। अदालत ने यह भी ध्यान में रखा कि उस समय अनुराग ठाकुर ने बिना किसी शर्त के बिना शर्त माफी दी थी।

अमित शाह ने लॉन्च की भारत टैक्सी

दिल्ली-एनसीआर में शुरू हुई

नईदिल्ली। भारत में कोऑपरेटिव मॉडल पर आधारित नई राइड-हेलिंग सेवा 'भारत टैक्सी' की आधिकारिक शुरुआत हो गई है। इस लॉन्च के साथ ही कैब एग्रीगेटर बाजार में ओला और उबेर को सीधी चुनौती मिलने की चर्चा तेज हो गई है।

दावा है कि यह सेवा ड्राइवरों को ज्यादा कमाई और यात्रियों को पारदर्शी किराया देगी। भारत टैक्सी का औपचारिक शुभारंभ केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में किया। लॉन्च के मौके पर भारत टैक्सी रैली भी निकाली गई, जिसमें ड्राइवरों और यात्रियों ने हिस्सा लिया।इस दौरान अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी ड्राइवरों को मुनाफे का मालिक बनाती है और उन्हें सम्मान व गरिमा प्रदान करती है। भारत टैक्सी के सीईओ

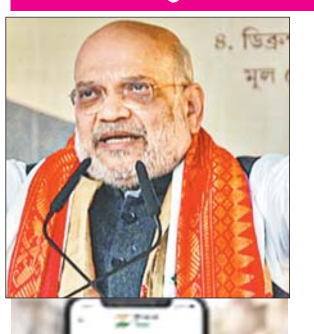

विवेक पांडे के अनुसार, फिलहाल ड्राइवरों से कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है। भविष्य में ड्राइवरों से 25-30 रुपये प्रति दिन का मामूली शुल्क लिया जा सकता है, जो निजी एप के कमीशन की तुलना में काफी कम होगा। हालांकि भारत टैक्सी को सहकारिता मंत्रालय का समर्थन प्राप्त है, लेकिन यह सरकारी सेवा नहीं है।

इसका संचालन सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। इस कोऑपरेटिव को अमूल सहित अन्य बड़े सहकारी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। भारत टैक्सी की योजना भविष्य में ड्राइवरों को सरकारी लोन उपलब्ध कराने की है, ताकि वे अपनी खुद की टैक्सी खरीद सकें। कंपनी का मानना है कि इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और ड्राइवर आत्मनिर्भर बनेंगे।

चरित्र शंका में पति बना हत्यारा, कुल्हाड़ी से पत्नी को उतारा मौत के घाट

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही। छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले से हत्या की एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। केंवची गांव के बैगापारा में एक पति ने अपनी पत्नी पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। हत्या के पीछे पति की पत्नी के चरित्र को लेकर शंका बताई जा रही है। यह मामला गौरेला थाना क्षेत्र का है। पुलिस के अनुसार, आरोपी पति राजेश बैगा अपनी पत्नी कुसुम बैगा के चरित्र को लेकर शंका करता था। इस बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। बीती रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद बढ़ गया और आरोपी ने कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी पर जोरदार हमला किया। इस हमले में गंभीर रूप से घायल कुसुम बैगा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना पर गौरेला पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी राजेश बैगा को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल, पुलिस आरोपी के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और आगे की जांच जारी है।

डीएसपी कल्पना वर्मा निलंबित, आदेश जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन ने डीएसपी कल्पना वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वे अभी दंतेवाड़ा जिले में पदस्थ हैं। इस संबंध में गृह (पुलिस) विभाग ने आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, शिकायत की प्राथमिक जांच में उनके खिलाफ वित्तीय लेनदेन, जांच में दिए गए कथनों और व्हाट्सएप चैट के तथ्यों में विरोधाभासी, कर्तव्य के दौरान अवैध आर्थिक लाभ प्राप्त करना, अपने पद का दुरूपयोग करना व अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप सामने आए हैं। यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत है। जिसे देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में कल्पना वर्मा का मुख्यालय पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।

बता दें कि डीएसपी कल्पना वर्मा और रायपुर के कारोबारी दीपक टंडन से जुड़े विवाद में जांच के दौरान कई गंभीर तथ्य सामने आए थे। सरकार के निर्देश पर एडिशनल एसपी स्तर पर कराई गई जांच की करीब 1475 पेज की रिपोर्ट तैयार कर शासन को सौंपी गई थी। इस रिपोर्ट में कई अहम खुलासे किए गए थे।

जांच रिपोर्ट में डीएसपी वर्मा और दीपक टंडन के बीच हुई व्हाट्सएप चैट सामने आई, जिनमें पुलिस विभाग से जुड़ी संवेदनशील और खुफिया जानकारियां साझा किए जाने का उल्लेख था, जो खुफिया जानकारी लीक करने जैसे गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं अब शासन ने एक्शन लेते हुए डीएसपी कल्पना वर्मा को निलंबित कर दिया है।

मॉडल तालाब से बदहाली तक पहुंचा गंगासागर, करोड़ों खर्च के बाद भी नहीं सुधरी स्थिति

जिम्मेदारों ने गंगासागर को बना दिया चारागाह, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार

बालोद। अविभाजित मध्यप्रदेश शासनकाल में निर्मित बालोद का ऐतिहासिक गंगासागर तालाब, जो कभी पूरे छत्तीसगढ़ के लिए मॉडल तालाब का दर्जा रखता था, आज पूरी तरह अपना अस्तित्व खो चुका है। इसे दूर से देखिए तो सुंदर-स्वच्छ होने की गलतफहमी हो सकती है लेकिन पास जाइये तो सपनों की नाव बदहाली के समंदर में डूबती नज़र आएगी। ये हालत तब जबकि नगर पालिका हर साल तालाब को संवारने के लिए लाखो का बजट पास कराता है। लेकिन पैसा कहां जाता है, ये एक रहस्य है। देखा जाए तो गंगासागर तालाब की पहचान स्टेट लेवल पर है। इसे मॉडल तालाब का भी दर्जा मिला है। इस दौर के नगर पालिका अध्यक्ष रहें यज्ञदत्त शर्मा ने इसे मॉडल तालाब के रूप में विकसित कराया था और यही कारण था कि गंगासागर को पूरे छत्तीसगढ़ में मॉडल तालाब का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन विडंबना देखिए कि जिस तालाब पर कभी राज्य को गर्व था, वही आज सत्ता, सिस्टम और सौंदर्यकरण की राजनीति का सबसे शर्मनाक उदाहरण बन चुका है, और आज तालाब जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी के लिए आय का एक प्रमुख साधन बन चुका है। जिम्मेदारों ने गंगासागर को चारागाह बना डाला है। बताया जाता है कि पिछ्ले 10 वर्षो में गंगासागर तालाब के लिए विभिन्न मदो से तकरीबन सवा करोड़ रूपए खर्च किए गए। यहां पर 27 लाख रुपये के डीएमएफ फंड से म्यूजिकल फाउंटेन लगाए गए। लेकिन नगरपालिका की इच्छाशक्ति के अभाव में यह फाउंटेन अब बदहाल हो चुका है। ट्रायल के बाद से ही फव्वारा बंद पड़ा है। फव्वारे का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा है। अभी 19.99 लाख एवं 19.88 लाख रुपये से वाटर सप्लाई पाइप लाइन वर्क, ट्यूब वेल, पाथवे डेंवेलपमेंट, प्लांटेशन, फेंसिंग बाउंड्री वॉल, गार्डन लाइटिंग पोल विद केबलिंग कम्प्लीट वर्क, बाउंड्री वॉल व गेट पेंटिंग वर्क के कार्य किये जा रहे है।

सियान सदन आ रहा कबाड़ रखने के काम

10 सालों तक नगर पालिका और प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और उस समय भी इस तालाब के सौंदर्यीकरण सहित अन्य कार्यों के लिए लाखों रूपए खर्च किए गए, तालाब के पानी की गंदगी को खत्म करने और पानी की सफाई के लिए तालाब को खाली भी कराया गया था। तात्कालिक नगर पालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने नौका विहार की भी शुरुआत कराई थी। कश्मीर की तर्ज पर इस तालाब में सोफा सेंट डिजाइन एवं गद्दा लगाकर नाव को तैयार कर तालाब में उतारा गया था। जिस पर लाखों रुपये खर्च किए गए थे, इसके बाद इसे आगे चलाने के लिए एक समूह को दे दिया गया था, नौका में सवारी करने का आनंद लेने वाले लोगों को 20 से 50 रुपये शुल्क भी लिया जाता था। महज कुछ माह वी भी बंद हो गया। एक साल पहले यहां के पानी के खाली करवाकर सफाई कराई गई थी, अभी भी सफाई के नाम पर पानी को मोटर पम्प के जरिये खाली करवाया जा रहा है। यह कहना गलत नहीं होगा कि 2016 के बाद से इसे संवारने के नाम लाखों रुपये का भ्रष्टाचार किया गया है, जो आज पर्यंत तक ट्रिपल इंजन की सरकार में भी जारी हैं। स्थिति आज भी बदहाल ही नजर आती है, बुजुर्गो के बैठने के लिए बनाया गया सियान सदन कबाड़ रखने के काम आ रहा है, सियान सदन में पैडल नाव को रखा गया है, जो कबाड़ में तब्दील हो गया है, जिसे डीएमएफ मद से खरीदा गया था। पैदल चलने के लिए बनाए गए रास्ते में लगे टाइल्स भी धस चुके है और बाउंड्री वॉल के रंग उड़ चुके तो कही बाउंड्री वॉल टूटी पढ़ी है।

सप्ताह भर में उखड़ रही पेंटिंग

वर्तमान में इस तालाब के सौंदर्यीकरण, पेंटिंग, ड्रेनेज सिस्टम और पानी को खाली करने का कार्य किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इस समय नगरपालिका, प्रदेश और केंद्र में ट्रिपल इंजन की सरकार काबिज है, लेकिन इस तालाब को दोनों ही पक्षों ने सिर्फ और सिर्फ चारागाह बनाया है, क्योंकि वर्तमान नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल में भी लाखों रूपये खर्च किए गए है, अभी डीएमएफ फंड से वाटर सप्लाई पाइप लाइन वर्क, ट्यूब वेल, पाथवे डेंवेलपमेंट, प्लांटेशन, फेंसिंग बाउंड्री वॉल, गार्डन लाइटिंग पोल विद केबलिंग कम्प्लीट वर्क, बाउंड्री वॉल व गेट पेंटिंग वर्क के कार्य किये जा रहे है, जिसके लिए लगभग 40 लाख रुपये की स्वीकृति डीएमएफ मद से की गई हैं।

एक नज़र में खर्च

बीते 10 सालों में गंगासागर तालाब में डेढ़ करोड़ रुपये से अधिक खर्च किये जा चुके है। गंगा सागर तालाब पार में आरसीसी नाली निर्माण फेस-1 में 18.81 लाख, तालाब पार में आरसीसी नाली निर्माण फेस-2 में 16.23 लाख, गंगासागर मे विसर्जन कुंड 3.00 लाख, फाउंटेन 1.50 लाख, चौपाटी सेंटर 10.09, पैडल बोट क्रय 4.95 लाख, सियान सदन 4.52 लाख, साफ-सफाई एवं गहरीकरण के लिए लाख 3.50 लाख, टाईल्स लगाने का कार्य में 10.00 लाख, उद्यान बाउण्ड्रीवाल निर्माण बोरखनन कार्य गेट निर्माण कार्य रिटेनिंग व निर्माण कार्य के लिए 15.99 लाख एवं सुविधा की व्यवस्था में 6.50 लाख रुपये खर्च किये गए, 27 लाख रुपये का म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया है। इसके साथ ही अध्यक्ष एवं पार्षद निधि तथा अन्य मदो से भी करीबन 20 लाख रुपये से अधिक खर्च किये गए है। अभी 19.99 लाख एवं 19.88 लाख रुपये से विभिन्न कार्य किये जा रहे है। बहरहाल, कभी बालोद की पहचान और गौरव रहा गंगासागर तालाब आज सवालों के घेरे में है और अब देखने वाली बात यह होगी कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारी इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए ठोस कदम उठाते हैं या फिर करोड़ों खर्च के बाद भी यह तालाब बदहाली की कहानी ही बयान करता रहेगा

कोसरिया यादव समाज रानीतराई सर्किल ने बेलौदी में मनाया गीता जयंती

गीता जीवन का सार : भूपेश बघेल

पाटन। मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समाज गंगा को प्रणाम करते हुए जय यादव जय माधव का जय घोष किए।उन्होंने समाज को एकजुटता दिखलाते हुए सामाजिक रीति रिवाज के साथ युवा पीढ़ी संकल्पित रहे। गलत कार्यों एवं नीतियों का खुलकर विरोध करे।हमेशा समाज हित में कार्य करते हुए आगे बढ़े। वर्तमान सरकार समाज को विघटन करने की दिशा में काम कर रही है, जिसे सामाजिक बंधु को समझने की जरूरत है। हमने आपके समाज हित में गौठान निर्माण,गोबर खरीदी,महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ सामाजिक भवन सहित सभी अधोसंरचना के लिए राशि स्वीकृति प्रदान की थी।आज केंद्रीय बजट में छत्तीसगढ़ को झुनझुना दिखला दिया। अध्यक्षता लच्छी राम यादव अध्यक्ष,कोसरिया यादव समाज सर्किल रानीतराई ने सभी अतिथियों का स्वागत उद्बोधन करते हुए सामाजिक संगठन को सुदृढ़ बनाने के संदेश दिए। मंच में विक्रम यादव संरक्षक, कोसरिया यादव समाज सर्किल रानीतराई, विशिष्ट अतिथि अशोक साहू पूर्व उपाध्यक्ष, जिला पंचायत दुर्ग, नोमिन हितेश ठाकुर सदस्य, जिला पंचायत दुर्ग, राजेश ठाकुर अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जामगांव आर, शंकर बघेल पूर्व सदस्य खाद्य बीज निगम दुर्ग, देवकुमार निषाद पूर्व सदस्य, मछुवारा कल्याण बोर्ड, कौशल चन्द्राकर उपाध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी, दीपमाला विजय साहू सदस्य, जनपद पंचायत पाटन, हुकुमचंद निषाद, सरपंच, भूपेन्द्र (छोटू) बघेल मंडल अध्यक्ष, रामाधार वर्मा समाज सेवी,विनोद वर्मा, भेदप्रकाश वर्मा मंचासिन रहे। सुबह सामाजिक पदाधिकारियों एवं बंधु ने कलश यात्रा, प्रतिभा सम्मान, युवक युवती परिचय, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा सामाजिक परिचर्चा किया गया। एक जोड़े का आदर्श विवाह का संपन्न हुआ। इस अवसर पर गोविंद यादव,विक्रम यादव, देवीचरण यादव, रामचंद,बरातू,शंकर यादव,अर्चना यादव,बोधन यादव, खुमेश्वरी यादव, सुधा राधे यादव नीलम यादव, गोकुल यादव, जीवन यादव, संजय यादव,भागवत यादव, निलेश, संतोष, दिलीप, रमेश सहित कोसरिया यादव सामाजिक बंधु उपस्थित रहे।

दिन से ज्यादा रात में हो रही है मुरूम और मिट्टी की चोरी, नही पहुंच रहा है जिम्मेदारों का हाथ

अम्लेश्वर। पाटन विधान सभा क्षेत्र के उत्तर पाटन के आसपास के ग्रामो में मुरुम माफियायों के द्वारा शासकीय एवं निजी जमीन पर अवैध रूप से मुरूम उत्खनन कार्य कर रहे है। भोले भाले किसानो की खेत को खोदकर मुरुम उत्खनन कर अवैध व्यवसाय कर रहे है। क्षेत्र के शासकीय भूमि पर भी मुरुम माफिया लोग मुरुम खोदकर निजी उपयोग मे इस्तेमाल कर है।

जिससे मवेशियों की चारा की समस्या उत्पन्न हो रही है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार लगातार मुरूम और मिट्टी चोर अवैध खनन कर अवैध फ्लटिंग में सप्लाई कर रहे है। सबसे ज्यादा मुरूम और मिट्टी के चोर अमलेश्वर में छुपे हुए हैं। जिस पर कार्यवाही करने से खनिज विभाग अपना हाथ खींच रही है। यह मुरूम और मिट्टी माफिया की पहुंच पकड़ इतनी है की यह लोग बेधड़क दिन में तो खुदाई करते हैं रात में और ज्यादा जेसीबी और हाईवे लगाकर खुदाई करते हैं जिससे शासन को लाखों रुपए की खनिज राजस्व का नुकसान हो रही है। अमेरी, करगा, गभरा के खेतो से निकल रही है बड़ी मात्रा में मुरूम।

पीली मिट्टी की परत को उखाड़ कर मुरूम खनन किया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि ये लोग मेन रोड को छोड़कर नहर नाली के किनारे बने सी सी रोड में हाईवा और जेसीबी को दौड़ाते हैं जिससे रोड खराब होने की भी आशंका आसपास के सरपंचों के द्वारा जताई जा रही है।जिस पर जिम्मेदार अधिकारी की हाथ नहीं पहुंच पा रही है। जिस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधी भी तत्काल अवैध मुरुम, मिट्टी उत्खनन कार्य पर रोक लगाकर मुरुम माफियो पर कड़ी कार्यवाही करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी पाटन राजस्व को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्यवाही करने की मांग भी पूर्व में किया गया है। उक्त विषय में मंडल अध्यक्ष अम्लेश्वर कमलेश चंद्राकर ने भी प्रजा नाराजगी जाहिर की है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर तेज़ी से अमलः दुर्ग नगर निगम ने बनाए 60 डॉग फीडिंग सेंटर

दुर्ग। सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग नगर निगम ने शहर में कुल 60 डॉग फीडिंग सेंटरों का निर्माण पूरा कर लिया है।निगम अधिकारियों के अनुसार ये सभी केंद्र निर्धारित समय-सीमा से पहले ही तैयार कर लिए गए, जिससे सड़क पर रहने वाले कुत्तों को नियमित भोजन और स्वच्छ पानी उपलब्ध कराया जा सके। इन सेंटरों में खाने और पानी के लिए अलग-अलग व्यवस्थाएँ की गई हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। कई स्थानों पर लोग भी आगे आकर इन केंद्रों पर स्वच्छ भोजन डाल रहे हैं और निगम की पहल को सहयोग दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा पशुओं की सुरक्षा और नियंत्रण के लिए दिए गए निर्देशों के अनुरूप नगर निगम ने सेंटर भी सक्रिय कर दिया है। यहाँ कुत्तों की नसबंदी, टीकाकरण और एंटी-रेबीज़ इंजेक्शन की पूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।विशेषज्ञ टीम नियमित रूप से कुत्तों को पकड़कर सेंटर में लाती है, जहाँ मेडिकल प्रक्रिया के बाद उन्हें उनके मूल क्षेत्र में वापस छोड़ा जाता है। नगर निगम आयुक्त अग्रवाल का कहना है कि शहर में कुत्तों की बढ़ती संख्या को मानवीय तरीके से नियंत्रित करना आवश्यक है, ताकि नागरिकों की सुरक्षा के साथ-साथ पशुओं के प्रति संवेदनशीलता भी बनी रहे। इसी उद्देश्य से सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। निगम आयुक्त सुमित अग्रवाल ने यह भी बताया कि आने वाले समय में डॉग फीडिंग सेंटरों की मॉनिटरिंग को और मजबूत किया जाएगा तथा लोगों को भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे निर्धारित स्थानों पर ही भोजन डालें, जिससे शहर में स्वच्छता बनी रहे।

प्रतियोगिता पंजीयन शुरू,राजेन्द्र पार्क पहुंचकर करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन

फ्लावर शो प्रतियोगिताओं के लिए खुला पंजीयन

दुर्ग। महापौर अलका बाघमार के मार्गदर्शन में दुर्ग द्वारा आगामी फ्लावर शो (पुष्प प्रदर्शनी) के भव्य आयोजन को लेकर डाटा सेंटर में आयुक्त सुमित अग्रवाल की अध्यक्षता में तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक में पर्यावरण प्रभारी काशीराम कोसरे, कार्यपालन अभियंता एवं उद्यान प्रभारी अनिल सिंह उपस्थित रहे। बैठक में आयोजन को इस वर्ष और अधिक भव्य व आकर्षक बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि यह मेगा फ्लावर शो दुर्ग के जीई रोड स्थित राजेन्द्र पार्क में आयोजित किया जाएगा। यहां विभिन्न प्रजातियों के रंग-बिरंगे फूलों की भव्य प्रदर्शनी लगाई जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजन को पिछले वर्षो की तुलना में अधिक वृहद स्वरूप दिया जाएगा, जिसमें फूलों के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के आकर्षक मॉडल भी प्रदर्शित किए जाएंगे। फ्लावर शो के दौरान केवल पुष्प प्रदर्शनी ही नहीं, बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं और कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिससे आयोजन और अधिक रोचक एवं जनसहभागिता से परिपूर्ण होगा। यह आयोजन शहरवासियों के लिए प्रकृति, कला और संस्कृति का अनूठा संगम बनेगा। महापौर अलका बाघमार एवं आयुक्त सुमित अग्रवाल के निर्देश पर पर्यावरण एवं उद्यानिकी विभाग प्रभारी काशीराम कोसरे के नेतृत्व में आयोजन किया जाएगा। पर्यावरण प्रभारी काशीराम कोसरे ने बताया कि प्रतियोगिताओं में भाग लेने के इच्छुक प्रतिभागी राजेन्द्र पार्क परिसर में पहुँचकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस फ्लावर शो का मुख्य उद्देश्य लोगों को प्रकृति से जोड़ना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और शहर के सौंदर्य को निखारना है।

25 वर्षों का उजाला: अहिवारा में रजत महोत्सव की धूम

दुर्ग। अहिवारा संभाग एवं वितरण केंद्र अहिवारा के संयुक्त तत्वाधान में वार्ड क्रमांक 12 स्थित मंगल भवन में छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2026 का भव्य और सफल आयोजन किया गया। राज्य स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों को समर्पित इस उत्सव में न केवल विकास की गाथा दोहराई गई, बल्कि बिजली विभाग की रीढ़ कहे जाने वाले उपभोक्ताओं और कर्मठ कर्मचारियों का सम्मान कर रिश्तों की नई मिसाल पेश की गई। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अध्यक्ष, जनपद पंचायत धमधा लीमन साहू और अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद अहिवारा विद्यानंद कुशवाहा उपस्थित रहे। विशिष्ट अतिथियों में विधायक प्रतिनिधि अहिवारा सतीश साहू, अध्यक्ष, सरपंच संघ दामिनी साहू, पार्षद द्वय अनुज साहू एवं पुरुषोत्तम वर्मा एवं अध्यक्ष, सहकारी समिति अहिवारा पवन जैन ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की शुरुआत में नगर पालिका परिषद के जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों और उपभोक्ताओं का पुष्पगुच्छ से गर्मजोशी भरा स्वागत किया गया।

मेन फॉर ट्री के महिला स्व सहायता समूहों को मानदेय भुगतान किया गया

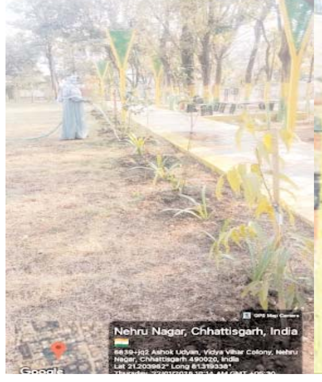

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई अंतर्गत वूमेन फॉर ट्री योजना अंतर्गत 12500 पौधा रोपण कर संधारण एवं रखरखाव करने वाली 125 महिलाओं को तीन माह का मानदेय जारी किया गया है। वूमेन फॉर ट्री योजना अंतर्गत कार्यरत 40 महिला स्व सहायता समूहों को माह अगस्त 2025, सितम्बर 2025 एवं अक्टूबर 2025 का मानदेय राशि रू. 27,23,802.00 का भुगतान एस.एन.ए. स्पर्श के माध्यम से मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य शहरी विकास अभिकरण, नवा रायपुर को दिनांक 03.12.2025 को प्रेषित किया गया था। उक्त राशि निगम के खाते में 02.02.2026 को प्राप्त होने के उपरांत तत्काल निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय द्वारा सभी 40 महिला स्व सहायता समूहों को मानदेय भुगतान किया गया है। शेष 2 माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2025 का मानदेय भुगतान हेतु शासन को लगभग 1 माह पूर्व देयक प्रेषित किया गया है। राशि प्राप्त होने पश्चात शेष 2 माह का मानदेय भी भुगतान किया जायेगा।

जोन आयुक्त ने किया निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन-2 वैशाली नगर अंतर्गत निर्माणाधीन डामरीकरण सड़क सहित उद्यान का निरीक्षण जोन आयुक्त येशा लहरे द्वारा किया गया। स्थानीय नागरिको से मिलकर उनकी समस्या से अवगत हुए। जोन आयुक्त ने वैशाली नगर स्थित सिंधु भवन मार्ग में निर्माणाधीन डामरीकरण सड़क का निरीक्षण किये। स्थानीय नागरिको का मांग था कि सुगम यातायात हेतु सड़क बनाया जाये। जिसे देखते हुए नवीन सड़क निर्माण किया जा रहा है, इस सड़क के निर्माण से नागरिको को आवागमन में सुविधा होगी। समीपस्थ प्राइवेट समिति द्वारा सुन्दर नगर पार्क बनाया गया है, जिसका अवलोकन किया गया। पार्क अच्छा बनाया गया है, जिसे समय-समय पर समिति द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। स्थानीय नागरिको से मुलाकात कर वहां की समस्या से अवगत हुए। उपस्थित नागरिको द्वारा उद्यान एवं सड़को पर प्रकाश व्यवस्था की मांग किया गया है, जिसे जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया गया है। निरीक्षण के दौरान सहायक अभियंता अर्पित बंजारे, जोन स्वास्थ्य अधिकारी शंकर साहनी, स्वच्छता निरीक्षक अंजनी सिंह उपस्थित रहे।

उप स्वास्थ्य केंद्र कोदवामहंत में निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित

शिविर में 17 मानसिक रोगियों सहित 25 मरीजों का हुआ ईलाज

मुंगेली। कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार तथा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. शीला साहा के मार्गदर्शन में विकासखंड लोरमी के उप स्वास्थ्य केंद्र कोदवामहंत में निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला नोडल अधिकारी व प्रभारी मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम मनोचिकित्सा अधिकारी डॉ. संजय ओबेरॉय, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नीरज शुक्ला एवं सोशल वर्कर विश्वनाथ चंद्राकर द्वारा मानसिक रोगियों को उचित परामर्श प्रदान करते हुए आवश्यक दवाइयां वितरित की गई। शिविर में 17 मानसिक रोगियों सहित 25 मरीजों का ईलाज किया गया। साथ ही सीएचओ के सहयोग से ग्राम के चार घरों में जाकर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों का उपचार किया गया।

राष्ट्रव्यापी हड़ताल को विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन का नैतिक समर्थन, काली पट्टी लगाकर करेंगे काम

कोरबा। केंद्र सरकार द्वारा लाये गए नए कानून लेबर कोड, पावर कम्पनियों के निजीकरण, ओपीएस की जगह यूपीएस लागू करने तथा संविदाकर्मियों को 10 साल की सेवा के बाद भी नियमित नहीं करने के विरोध में आगामी 12 फरवरी 2026 को प्रस्तावित राष्ट्रव्यापी हड़ताल को अखिल भारतीय विद्युत कामगार महासंघ से सम्बद्ध एवं मान्यता प्राप्त एकमात्र ट्रेड यूनियन संगठन छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन ने नैतिक समर्थन देने का फैसला किया है। इस संदर्भ में जनता यूनियन के प्रांताध्यक्ष अनिल द्विवेदी ने बताया वे छत्तीसगढ़ में कार्यरत बिजलीकर्मियों से 12 फरवरी के इस अखिल भारतीय हड़ताल को बाहर से समर्थन देने तथा कर्मचारी हित, हक और सम्मान के लिए आवाज बुलंद करने का आह्वान करते हैं। उन्होंने विद्युत कम्पनी में कार्यरत कर्मचारियों से आह्वान करते हुए कहा है कि 12 फरवरी को कर्मचारी ड्यूटी पर आने के बाद काम शुरू करने से पहले अपने अपने कार्यालय के समक्ष केंद्र सरकार की दमनकारी श्रम नीति तथा अन्य प्रस्तावित मांगों की वादाखिलाफी के विरोध में नारेबाजी करें तथा सम्पूर्ण दिवस काली पट्टी बांधकर काम करें। जनता यूनियन के प्रांताध्यक्ष अनिल द्विवेदी और प्रांतीय महासचिव अजय बाबर ने संयुक्त रूप से बताया कि जनता यूनियन इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 एवं नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पालिसी 2026 को वापस लेने, न्यूक्लियर पावर सेक्टर में निजी घराने के बडे पैमाने पर प्रवेश हेतु बनाये गए ''शांति एक्ट'' को वापस लेने के साथ ही उत्पादन के क्षेत्र में जॉइंट वेंचर समाप्त करने के साथ ही ट्रांसमिशन सेक्टर में टैरिफबेस्ड काम्पटेटिव बिडिंग के नाम पर हो रहे।

नो पार्किंग में खड़े कई गाडियों पर लगाया लॉक

ट्रैफिक पुलिस ने अपनाया सख्त रुख

कोरबा। जिले में 37वें सडक् सुरक्षा जागरूकता माह के दौरान लगातार चलाए गए अभियान से यातायात व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला है। बावजूद इसके कुछ वाहन चालक अब भी ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करते नजर आ रहे हैं। ऐसे मामलों में ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई भारी वाहनों को लॉक कर चालकों पर पेनल्टी लगाई। यह कार्रवाई शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाके सर्वमंगला चौक, हसदेव कैनाल जोड़ा पुल, राताखार तथा दारी रूमगरा क्षेत्र के ध्यानचंद चौक के आसपास की गई। इन स्थानों पर भारी वाहनों को नो पार्किंग जोन में मनमाने तरीके से खड़ा कर दिया गया था, जिससे यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही थी और आम लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस की पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने काफी मशक्कत करते हुए सडक् किनारे खड़े वाहनों को हटवाया और यातायात को सुचारू कराया। नियम तोडने् वाले वाहन चालकों के खिलाफ लॉक लगाने की कार्रवाई करते हुए जुर्माना भी वसूला गया। यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतिश ठाकुर, डीएसपी ट्रैफिक डीके सिंह के मार्गदर्शन तथा निरीक्षक तेज यादव के नेतृत्व में की गई।

संक्षिप्त समाचार

छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 7 करोड़ रुपये के धान शॉर्टेज केस में डीएमओ अभिषेक मिश्रा निलंबित

रायपुर। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की मियाद दो दिनों के लिए बढ़ाई गई है. इस बीच कवर्धा में धान पर अजब गजब बयान देने वाले डीएमओ अभिषेक मिश्रा को निलंबित किया है। यह कार्रवाई प्रबंध संचालक, राज्य स्तर रायपुर द्वारा मीडिया में भ्रामक जानकारी देने के आरोप में की गई है। निलंबन के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप की स्थिति बनी हुई हैछत्तीसगढ़ के कवर्धा में 7 करोड़ रुपये के धान शॉर्टेज केस में डीएमओ अभिषेक मिश्रा पर कार्रवाई हुई है। यह पूरा मामला 7 करोड़ रुपये के धान की गड़बड़ी से जुड़ा हुआ है। जब मीडिया ने धान शॉर्टेज को लेकर डीएमओ अभिषेक मिश्रा से सवाल किए, तो उन्होंने इसका कारण मौसम की मार, चूहा और दीमक द्वारा धान खाये जाने को बताया। इस बयान के बाद मामला और तूल पकड़ लिया। सोशल मीडिया से लेकर प्रदेशभर में इस बयान की तीखी आलोचना हुई। इसके बाद प्रबंध संचालक रायपुर द्वारा यह मानते हुए कि डीएमओ ने मीडिया में भ्रामक और गैर-जिम्मेदाराना बयान दिया है। साल 2024-25 में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी कर उसे चारभाठा स्थित धान संग्रहण केंद्र में संग्रहित किया गया था। वर्ष 2026 की धान खरीदी से पूर्व जब पुराने धान का भौतिक सत्यापन किया गया, तो करीब 26 हजार क्विंटल धान की कमी पाई गई, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 करोड़ रुपये आंकी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक जांच समिति गठित की गई। जांच में यह सामने आया कि तत्कालीन संग्रहण केंद्र प्रभारी प्रितेश पांडेय की भूमिका संदेहास्पद रही है। साथ ही संग्रहण केंद्र में लगे सीसीटीवी कैमरों से छेड़छाड़ के भी साक्ष्य मिले। इसके बाद प्रशासन ने प्रितेश पांडेय को पहले ही निलंबित कर दिया था। इसी मुद्दे पर मीडिया ने अभिषेक मिश्रा से सवाल पूछे थे, जिस पर उन्होंने चूहा और दीमक वाला बयान दिया था, इसी को लेकर यह कार्रवाई हुई है।

दो महिलाओं ने अपने ही सहेली को उतारा मौत के घाट,गांवभर में कर रही थी बदनाम

रायपुर। जिले में एक महिला से बर्बरता के बाद उसकी ही सहेलियों ने पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया. आरोपियों ने पहले महिला के प्राइवेट पार्ट पर जबरदस्ती लाल मिर्च डाल दिया. आपा खो चुकी दोनों आरोपी महिला ने डंडे से जमकर पीट, साथ ही लात-घूंसों से हमलाकर हत्या कर दी. मृतिका की पहचान सुमित्रा नेताम (37) के रूप में हुई है. पुलिस की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि वारदात समाज में बदनाम करने और चरित्र पर आरोप लगाने की रंजिश के कारण अंजाम दिया गया है. मृतका की पहचान सुमित्रा नेताम (37) के रूप में हुई है. पूरा मामला मैनपुर ब्लाक के शोभा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गरीबा का है.जानकारी के मुताबिक, आरोपी सुगतिन नेताम (36) और ईतवारिन बाई (46) के चरित्र को लेकर सुमित्रा गांव में लोगों के बीच आरोप लगाने लगी थी, जिससे उनकी सामाजिक छवि धूमिल हो रही थी. इसी बात को लेकर तीनों के बीच लंबे समय से तनाव बना हुआ था. घटना के दिन दोनों आरोपी महिलाएं सुमित्रा को सबक सिखाने के इरादे से उसके घर पहुंची थी. आरोप है कि आरोपियों ने सुमित्रा के साथ गंभीर शारीरिक हिंसा की. दोनों महिलाओं ने सुमित्रा के घर पहुंचकर पहले उसके गुप्तांग में लाल मिर्च और अन्य ज्वलनशील पदार्थ डालकर तड़पाया, फिर सीने पर चढ़कर डंडे और लात-घूंसों से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद आरोपी फरार होने की कोशिश में थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया. नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की. शव का पोस्टमॉर्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया गया है.

रायपुर में जुटेंगे विभिन्न देशों में बसे छत्तीसगढ़ी, 27-28 मार्च को प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव

रायपुर। प्रदेश के विकास में प्रवासी छत्तीसगढ़ियों की सहभागिता को सशक्त बनाने के उद्देश्य से 27 एवं 28 मार्च को राजधानी रायपुर में प्रवासी छत्तीसगढ़ कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। यह कॉन्क्लेव उत्तर अमेरिका छत्तीसगढ़ प्रवासी संघ तथा छत्तीसगढ़ एनआरआई संघ के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। इस दो दिवसीय आयोजन में भारत से बाहर विभिन्न देशों में निवासरत छत्तीसगढ़ के रहवासी सहभागिता करेंगे। इस कॉनक्लेव के लिए पंजीयन जल्द शुरू होगा। कॉन्क्लेव के माध्यम से प्रवासी छत्तीसगढ़ियों को प्रदेश के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक विकास से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, रोजगार सृजन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन एवं उद्योग विकास स्टार्टअप विकास जैसे विषयों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा। साथ ही, प्रवासी छत्तीसगढ़ियों के अनुभव एवं संसाधनों के माध्यम से राज्य के विकास में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर चर्चा होगी। इस कॉन्क्लेव का उद्देश्य प्रदेश और प्रवासी छत्तीसगढ़ी समाज के बीच संवाद को सुदृढ़ करना तथा सहयोग की नई संभावनाओं को तलाशना है। यह आयोजन छत्तीसगढ़ की पहचान को वैश्विक स्तर पर और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा। कॉन्क्लेव में विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञ, उद्यमी, सामाजिक कार्यकर्ता एवं विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि प्रवासी छत्तीसगढ़ी प्रदेश की अमूल्य पूंजी हैं।

आरंग की सड़कों पर विकास की रफ्तारः मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की पहल से 2155.97 लाख की बड़ी मंजूरी

रायपुर। आरंग विधानसभा क्षेत्र में विकास अब घोषणा नहीं, ज़मीनी सच्चाई बनता जा रहा है। क्षेत्र की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाते हुए छत्तीसगढ़ शासन ने सड़क विकास की बड़ी योजना को हरी झंडी दे दी है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहेब की सतत पहल और प्रभावी समन्वय का परिणाम है। लोक निर्माण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत जिला रायपुर के गोढ़ीङ्कतोड़गांवङ्कबड़गांव मार्ग के 9.00 किलोमीटर चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए ?2155.97 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना में सड़क निर्माण के साथ-साथ पुल-पुलिया का निर्माण भी शामिल है, जिससे क्षेत्रीय यातायात को स्थायी समाधान मिलेगा। इस सड़क के उन्नयन से न केवल आवागमन सुगम होगा।

लोकभवन में मनाया गया 6 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस

पहचान भले ही अलग हो लेकिन सभी राज्यों की आत्मा एक भारत में हैं

■ राज्य की स्थापना के मूल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता दिखाता

रायपुर/ संवाददाता

राज्यपाल श्री रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में आज राजभवन में 6 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की पहचान भले ही अलग-अलग हो लेकिन इन सब की आत्मा एक भारत में है। केन्द्र सरकार के एक भारत-श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत विविधता में एकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्य एक दूसरे का स्थापना दिवस मनाते है। इसी कड़ी में आज लोकभवन के छत्तीसगढ़ मण्डपम में आंध्रप्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब, झारखंड और नागालैण्ड राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों का स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर श्री डेका ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रथाओं के ज्ञान का आदान-प्रदान करना है जो आपसी समझ और सद्भाव को बढ़ावा देगा, जिससे भारत की एकता और अखंडता मजबूत होगी। इस परिप्रेक्ष्य में आज का कार्यक्रम एक गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि हर राज्य का स्थापना दिवस, उस राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन होता है। राज्य की समृद्धि और विकास का गवाह यह दिन हमें अपने राज्य की स्थापना के मूल उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का रास्ता दिखाता है। इन राज्यों का स्थापना दिवस, केवल उनके विकास की यात्रा का उत्सव नहीं है बल्कि भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है। उन्होंने विभिन्न राज्यों

की विशेषताओं को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि देश के विकास में आंध्रप्रदेश का शानदार योगदान है। यह राज्य मछली के लिए प्रसिद्ध है। यह तिरूपति बालाजी की देव भूमि है। इसी तरह पंजाब वीरों की भूमि है। गुरूतेग बहादुर के बलिदान को सब जानते है। भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व समुदाय में पंजाबियों का बहुत योगदान है। हरियाणा का उल्लेख करते हुए कहा कि यह राज्य प्राचीन परंपरा का मूलभूत केंद्र है। यह वही भूमि जहां से महाभारत का संदेश पूरी मानवता तक पहुंचा। झारखण्ड राज्य खनिज का हब है। चंडीगढ़ बहुत सुंदर और नियोजित प्रदेश है। नागालैण्ड बहुत खूबसुरत राज्य है। यहां की जनजातीय संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। इस राज्य के लोगों की बहादुरी की कहानियां दुसरों को प्रेरित करती हैं। श्री डेका ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम हमारे बीच संवाद, सहयोग और सद्भाव को और मजबूत करता है। समारोह में विभिन्न राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने अपने राज्यों की विशेषताओं, परंपरा, संस्कृति पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने विभिन्न राज्यों की संस्कृति एवं लोक परंपरा आधारित संस्कृति कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी। विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को राज्यपाल ने राजकीय गमछा और स्मृति चिन्ह भेंट किया। उन्होंने भी राज्यपाल को अपने राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना सहित अन्य अधिकारी, वनवासी आश्रम की छात्राएं, महिलाएं एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

बजट में अब महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि आर्थिक प्रगति में सहभागी' माना गया है

रायपुर, । संवाददाता

भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. किरण बघेल ने कहा है कि केन्द्रीय बजट-2026-27 ने 'महिला विकास' से आगे बढ़कर 'महिला नेतृत्व वाले विकास' पर ध्यान केंद्रित किया है। इस बजट का सबसे क्रांतिकारी कदम 'शी-मार्ट' की घोषणा है, जो ग्रामीण महिला उद्यमियों की आर्थिक शक्ति को एक नई पहचान देने वाला है। डॉ. (श्रीमती) बघेल ने कहा कि केन्द्र सरकार अब महिलाओं को केवल 'लाभार्थी' नहीं, बल्कि 'आर्थिक प्रगति में सहभागी' के रूप में देख रही है। शी-मार्ट जैसे प्रयास ग्रामीण अर्थव्यवस्था को औपचारिक रूप देंगे और महिलाओं को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ेंगे। यह 'कल्याण' से 'सशक्तीकरण' की ओर एक बड़ा संरचनात्मक बदलाव है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. (श्रीमती) बघेल ने कहा कि शी-मार्ट योजना महिलाओं को ऋण से उद्यम की ओर अग्रसर करेगी। शी-मार्ट योजना, जिसका अर्थ 'सेल्फ-हेल्प इन्ट्रेप्रेन्योर मार्ट' है, 'लखपति दीदी' कार्यक्रम की अगली कड़ी है। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को केवल ऋण लेने वाली श्रेणी से निकालकर 'व्यवसाय स्वामी' बनाना है। ये मार्ट ग्रामीण महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों (हस्तशिल्प, कृषि उत्पाद, प्रसंस्कृत खाद्य) को सीधे बाजार और ग्राहकों से जोड़ेंगे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। इसके लिए 'इनोवेटिव फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स' और क्रेडिट गारंटी जैसे आधुनिक वित्तीय

साधनों का उपयोग किया जाएगा। डॉ. (श्रीमती) बघेल ने कहा कि लखपति दीदी-2.0 के तहत सरकार ने 2027 तक 3 करोड़ लखपति दीदियाँ बनाने का लक्ष्य रखा है। बजट में अब तकनीक और डिजिटल वित्तीय साक्षरता पर जोर दिया गया है। वर्तमान में लगभग 2.5 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं (जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक है)। अब उन्हें उन्नत तकनीकी प्रशिक्षण देकर उनके व्यवसायों को बड़े पैमाने पर ले जाया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉ. (श्रीमती) बघेल ने कहा कि महिलाओं की उच्च शिक्षा और कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। छात्राओं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली लड़कियों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का प्रस्ताव है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में लड़कियों के नामांकन को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा। आर्थिक गलियारों के पास 5 नई 'यूनिवर्सिटी टाउनशिप' बनाई जाएंगी।

मनरेगा से बदली लोमेश साहू की जिंदगी,पक्का पशु शेड बना तरक्की का सहारा

■ साथ ही, गोबर से जैविक खाद बनाकर वे अपनी खेती में उपयोग कर रहे हैं, जिससे खेती की लागत भी कम हो गई

रायपुर/ संवाददाता

कहते हैं कि मजबूत इरादों और सही सरकारी योजना का साथ मिल जाए तो जीवन की राह आसान हो जाती है। कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत चरडोंगरी के रहने वाले गौ-पालक श्री लोमेश साहू की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। मनरेगा योजना ने उनके जीवन में बड़ा बदलाव लाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की। लोमेश साहू का परिवार खेती और पशुपालन पर निर्भर था। उनके पास गाय-भैंस तो थीं, लेकिन उन्हें रखने के लिए पक्का शेड नहीं था। कच्चे शेड में बरसात के समय कीचड़ और गंदगी हो जाती थी। गोबर और गौमूत्र के कारण सफाई रखना मुश्किल हो जाता था, जिससे पशु बीमार पड़ते थे और दूध उत्पादन भी कम हो जाता था। आर्थिक तंगी के कारण पक्का शेड बनवाना उनके लिए बहुत कठिन था। इसी बीच मनरेगा योजना के तहत उन्हें 53 हजार रुपये की लागत से पक्का पशु शेड बनाने की स्वीकृति मिली। निर्माण के दौरान उन्हें 36 मानव-दिवस का रोजगार भी मिला और मजदूरी की राशि सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुई। ग्राम पंचायत के सहयोग से मजबूत और साफ-सुथरा पशु शेड बनकर तैयार हो गया, जिससे उनकी सबसे बड़ी समस्या दूर हो गई। पक्का शेड बनने के बाद उनके पशु सुरक्षित और स्वस्थ रहने लगे, जिससे दूध उत्पादन में भी बढ़ोतरी हुई। आज उनके पास 12 गाय और 2 भैंस हैं और वे प्रतिदिन लगभग 50 से 60 लीटर दूध का उत्पादन कर रहे हैं। इससे उन्हें हर महीने करीब 40 से 45 हजार रुपये की शुद्ध आय होने लगी है। साथ ही, गोबर से जैविक खाद बनाकर वे अपनी खेती में उपयोग कर रहे हैं, जिससे खेती की लागत भी कम हो गई है। लोमेश साहू कहते हैं कि मनरेगा से मिला यह पशु शेड उनकी तरक्की की नींव साबित हुआ है। अब पशु सुरक्षित हैं, साफ-सफाई बनी रहती है और आय भी बढ़ गई है। इस योजना ने उनके परिवार को आत्मनिर्भर बना दिया है। आज वे न केवल अपने परिवार का बेहतर तरीके से पालन-पोषण कर रहे हैं, बल्कि गांव के अन्य किसानों के लिए भी एक प्रेरणा बन गए हैं।

भाजपा की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा-दीपक..

■ कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से मिली सशर्त जमानत, आज होंगे रिहा

रायपुर/ संवाददाता

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि हमारा भाजपा की गलत नीतियों एवं आतंक के विरुद्ध संघर्ष जारी रहेगा। आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए कवासी लखमा ने कहा कि पिछले दिनों कांग्रेस विधायक कवासी लखमा को शराब घोटाले के मामले में ईडी और ईओडब्ल्यू द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था जिसके चलते वे रायपुर सेंट्रल जेल में पिछले एक साल से जेल में बंद थे। उन पर आबकारी मंत्री रहते हुए करोड़ों रुपये का घोटाला करने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं उन्होंने 2 सौ करोड़ रुपये का एक सीमेंट संयंत्र भी जगदलपुर में खरीदा है। जिसको लेकर जांच जारी है। इधर दीपक बैज ने कहा कि इस पूरे प्रकरण के विरुद्ध हमने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था आज कवासी लखमा को सशर्त जमानत मिल गई है। पूरी औपचारिकता के पश्चात चार बजे बाद रिहा कर दिया जाएगा। आज बड़ी संख्या में उनके समर्थन जेल पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मनरेगा बचाव धान खरीदी, विद्युत कटौती एवं बिजली बिल में ऊर्जा प्रभार जोड़ने के कारण किसान एवं आम जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि राज्य में भाजपा शासन काल में किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है जिसके विरुद्ध आज हमने जिलाधीश कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया है।

कवासी लखमा की जमानत सत्य की जीत - कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं विधायक कवासी लखमा को अंततः सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलना स्वागत योग्य है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि एक बार फिर सत्य की जीत हुई है और यह साबित हो गया कि सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। कवासी लखमा को भाजपा की केंद्र एवं राज्य सरकार ने षडयंत्र पूर्वक कथित शराब घोटाले में फसाया था। एक वरिष्ठ आदिवासी नेता को जेल में बंद राजनीतिक विद्वेष के कारण किया गया था, सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है। कांग्रेस पार्टी अदालत के फैसले का स्वागत करती है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी।

कनवेंशन सेटर की रूपरेखा पर भी की गई चर्चा

शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय के फेस-2 का कार्य शीघ्र होगा प्रारंभ

■ शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय के फेस-2 का कार्य शीघ्र होगा प्रारंभः श्री सोनमणि बोरा

रायपुर/ संवाददाता

नवा रायपुर में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय का राज्योत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कर कमलों से लोकार्पण एवं छत्तीसगढ़ आदिवासी संग्रहालय का मई 2025 में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा लोकार्पण पश्चात, इनकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता के बाद अब शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय फेस-2 का कार्य शीघ्र ही प्रारंभ किया जाएगा। प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने इस संबंध में आज आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर स्थित सभाकक्ष में आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट एवं विभागीय अधिकारियों के साथ आवश्यक बैठक कर कार्ययोजना के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। प्रमुख सचिव श्री बोरा ने बताया कि फेस-2 के अंतर्गत एक कैफेटेरिया, गढ़ कलेवा एवं अन्य दुकानें खोली जानी हैं इस संबंध में अंतिम रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। फेस-2 के अंतर्गत ही आकर्षक बागवानी, परिसर के भीतर स्थित नंद सागर का सौंदर्यीकरण, फॉउंटेन एवं पार्किंग की बेहतर व्यवस्था की जाएगी। बैठक में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान परिसर में स्थित 100 सीटर छात्रावास के पास निर्माणाधीन कनवेशंन सेटर की रूपरेखा पर भी चर्चा की गई। इसके डिजाइन एवं लेआउट पर विस्तृत चर्चा कर आवश्यक संशोधन करने के निर्देश दिए। इसपर आगामी बैठक में चर्चा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि इस कनवेशंन सेटर में एक ऑडिटोरियम, आर्ट गैलरी, प्रदर्शनी हॉल, मीटिंग रूम, प्रशासनिक भवन, फूड कोर्ट इत्यादि की व्यवस्था रहेगी। उल्लेखनीय है कि शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत सरकार द्वारा गणतंत्र दिवस, 26 जनवरी, 2026 के अवसर पर आयोजित परेड में इस संग्रहालय को प्रदर्शित किया गया। इससे छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जनजातीय वीर नायकों की अमर गाथाओं, उनकी देश भक्ति, अद्मय साहस और बलिदान की परंपरा को नई पीढ़ी को जानने समझने का अवसर राष्ट्रीय मंच पर प्राप्त हुआ। इस संग्रहालय के उद्घाटन के बाद तीन माह में लगभग एक लाख से अधिक पर्यटकों द्वारा भ्रमण कर लिया गया है। बैठक में कांकेर एवं कोडांगांव में राजस्व/वन भूमि में निर्मित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के हस्तांतरण प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में संचालक, टीआरटीआई श्रीमती हिना अनिमेष नेताम, उपसचिव श्री बी.के.राजपूत, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री जितेन्द्र गुप्ता, श्री आर.एस.भोई, उपायुक्त श्री विश्वनाथ रेडडी ,कार्यपालन यंत्री श्री त्रिदीप चक्रवर्ती, उपयंत्री श्री गुप्ता एवं श्री यशवंत राव सहित आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

संपादकीय

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते से राहत की उम्मीद, पर कई सवाल अब भी बाकी

पिछले कई महीने से अमेरिका की ओर से लागू शुल्क नीति के कारण जहां दुनिया भर में व्यापार युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो रही थी, वहीं भारत के सामने मुख्य चुनौती अपने लिए बेहतर विकल्प तलाश करने की थी। अब सोमवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा, उससे यही लगता है कि भारत और अमेरिका के बीच परस्पर हित पर आधारित एक समझौता आकार ले सकता है।ट्रंप ने इस संबंध में सोशल मीडिया पर दावा किया कि अमेरिका-भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति बनी है, जिसके तहत शुल्क को पचास फीसद से घटा कर अठारह फीसद किया जाएगा। दूसरी ओर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत भी इसी तरह अमेरिका के खिलाफ अपनी शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ेगा। दोनों देशों की ओर से ऐसी घोषणा को शुल्क के मसले पर महीनों से जारी तनाव के बाद अमेरिका और भारत की नीतियों में अब एक बड़े बदलाव का सूचक माना जा रहा है। हालांकि यह साफ होना बाकी है कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौता अंतिम तौर पर किस स्वरूप में सामने आता है और उसमें बनी सहमति कहां तक परस्पर हित सुनिश्चित करती है। मगर फिलहाल सामने आई खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने जिस तरह शुल्क में कमी करने की बात कही है, उसके अमल में आने पर भारत को राहत मिल सकती है।दरअसल, कई ऐसे क्षेत्र हैं, जिन पर अमेरिकी नीतियों का असर पड़ना शुरू हो चुका था। इसके बावजूद भारत ने अमेरिका की ओर से जरूरत से ज्यादा सख्त शर्तों की वजह से समझौते के लिए सहमति देने को लेकर सावधानी बरती और इससे उपजी मुश्किल का विकल्प तलाशने की कोशिश जारी रखी। यही वजह है कि अमेरिका की ओर से शुल्क को पचास फीसद कर देने की घोषणा के बाद भी भारत ने रूस से तेल की खरीद जारी रखी। यों ट्रंप ने दावा किया है कि अब भारत ने रूस से तेल की खरीद बंद करने और अमेरिका से कहीं अधिक मात्रा में तथा संभावित रूप से वेनेजुएला से भी तेल खरीद पर सहमति जताई है। हालांकि भारत और रूस के बीच जैसे संबंध रहे हैं, उसके मद्देनजर यह देखने की बात होगी कि रूस से तेल की खरीद पूरी तरह बंद करने के सवाल पर भारत क्या रुख अपनाता है।इसके अलावा, भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के किसी ठोस निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाने का एक बड़ा कारण यह था कि भारत कृषि क्षेत्र को पूरी तरह खोलने को लेकर राजी नहीं था। व्यापार समझौते के अंतिम रूप में भारत कृषि जैसे सबसे संवेदनशील मुद्दे पर क्या हासिल करता है, लेकिन किसानों की ओर से कई तरह की चिंताएं सामने आई हैं।

जहां तक इस कुत्सित सोच की वैधानिक न्यायसंगतता के आधार का सवाल है तो भारतीय संविधान समानता (अनुच्छेद 14-16) और सामाजिक न्याय पर जोर देता है, लेकिन अतीत के अपराधों के लिए वर्तमान निर्दोषों को 'सजा' देना प्रतिशोधात्मक लगता है, जो अबतलक बदस्तूर जारी है। अतीत के भेदभाव को आधार बनाकर सवर्ण समाज के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को दंडित करने या आरक्षण जैसी नीतियों से बांधना न्यायसंगतता के सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि यह व्यक्तिगत योग्यता को नजरअंदाज कर सामूहिक दोषारोपण करता है। इसलिए यक्ष प्रश्न है कि अतीत में हुए भेदभाव पर सवर्णों के वर्तमान-भविष्य को कानूनी शिकंजे में कसना दलित-ओबीसी नेतृत्व की न्यायसंगतता का तकाजा नहीं है!

अतीत में हुए भेदभाव पर सवर्णों के वर्तमान-भविष्य को कानूनी शिकंजे में कसना न्यायसंगतता का तकाजा नहीं?

(कमलेश पांडे)

लिहाजा, उन्मुक्त हृदय से उनके मौजूदा प्रगतिशील नेताओं को गहराई पूर्वक विचार करना चाहिए और अपने पूर्वजों के प्रतिगामी नजरिए को बदलकर स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व के राष्ट्रव्यापी लोकतांत्रिक भाव को मजबूत करना चाहिए। अन्यथा सामाजिक विघटन को परमाण्विक प्रक्रिया तेज होगी और इससे पैदा हुए जनविद्वेष की आग में देर-सबेर हरेक शांतिप्रिय लोगों के भी झुलसने का आसन्न खतरा बना रहेगा। ऐसा इसलिए कि यह नीतिगत, वैधानिक और रणनीतिक सवाल है जिसे कूटनीतिक स्वार्थवश विदेशों से हवा दी गई, इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया, जिससे जातिविहीन हिंदुत्व के राष्ट्रवादी विचार को गहरा धक्का लगा है।

जहां तक इस कुत्सित सोच की वैधानिक न्यायसंगतता के आधार का सवाल है तो भारतीय संविधान समानता (अनुच्छेद 14-16) और सामाजिक न्याय पर जोर देता है, लेकिन अतीत के अपराधों के लिए वर्तमान निर्दोषों को 'सजा' देना प्रतिशोधात्मक लगता है, जो अबतलक बदस्तूर जारी है। इसलिए कहीं न कहीं यह सामाजिक एकता को कमजोर करता प्रतीत होता है। वहीं, जहां तक इस आशय की हुई क्षतिपूर्ति की अवधारणा की बात है तो यह अतीत-वर्तमान के अंतर्संबंध पर आधारित है, परंतु यह तब न्यायपूर्ण होती है जब यह पीड़ितों को शक्ति प्रदान करे, न कि नए भेदभाव को जन्म दे।

खासकर भारतीय संदर्भ में जातिगत भेदभाव के विरुद्ध अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग (एससी/एसटी*ओबीसी) आरक्षण ऐतिहासिक अन्याय सुधारने का ब्रितानी और भारत सरकार का विषैला सियासी प्रयास है, किंतु यूजीसी बिल (2026) जैसे नए प्रतिगामी नियमों व

कदमों के दुरुपयोग की आशंका पैदा करते हैं, जहां झूठे आरोप सामाजिक कड़वाहट बढ़ा सकते हैं। यह ठीक है कि रोहित वेमुला या पायल तडवी जैसे मामले दर्दनाक हैं, लेकिन नीतियां ऐसी हों जो योग्यता और समावेश को प्राथमिकता दें।

ऐसा इसलिए कि एक तो छात्र राजनीति से पढ़ाई-लिखाई पर आंच आई, विश्वविद्यालय कैम्प्स की गरिमा गिरी है और अब उन्हें जातीय नजरिए से बांटना आग से खेलने जैसा मूर्खता भरा सियासी कदम है। इससे सांप्रदायिक राष्ट्वाद की तरह ही जातिवादी राष्ट्वाद की भावना को बल मिलेगा।

इसलिए बेहतर होगा कि हमारा सत्ता प्रतिष्ठान वैकल्पिक दृष्टिकोण विकसित करे। मेरे विचार से शिक्षा, जागरूकता और आर्थिक उत्थान से भेदभाव दूर करना अधिक न्यायसंगत है, क्योंकि संस्थागत भेदभाव को समाप्त करने से भविष्य स्वाभाविक रूप से समान बनेगा।

कहना न होगा कि अतीत को याद रखना जरूरी है, किंतु वर्तमान को उसके बोझ से मुक्त रखना ही सामाजिक प्रगति का आधार है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिन्नावादी सांप्रदायिक सोच से निरंतर झुलस रहे भारतीय उपमहाद्वीप को ब्रितानी और अंबेडकरवादी/लोहियावादी जातिवादी सोच से विखंडित करने का जो मूर्खतापूर्ण सरकारी प्रयास जारी है, उससे जब सत्तर साल बाद भी मुट्ठीभर दलित-आदिवासी-ओबीसी की ही भलाई हो पाई है और उनमें भी नवसामंती भावना प्रबल हुई है, जिससे विखंडित जनादेश आने से अवसरवाद बढ़ा है। यह भारत के समावेशी विकास में भी अब बाधक बनता प्रतीत होता है।

यह ठीक है कि भारत में जातिगत भेदभाव के लिए आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब सवर्णों को भी नौकरी में 10 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, लेकिन अन्य सहूलियत उन्हें मिलना अभी बाकी है। हालांकि, भारत की जातिवादी आरक्षण वाली सोच के समक्ष कुछ मजबूत चुनौतियां भी हैं। अगड़े भारतवासी इन्हें जाति की बजाए आर्थिक करने की मांग निरंतर करते आये हैं। वैश्विक

क्षतिपूर्ति मुख्यतः सकारात्मक कार्रवाई के रूप में लागू होती है, जो ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने का प्रयास करती है। क्योंकि यह आरक्षण, कल्याणकारी योजनाओं और विधायी सुरक्षा के माध्यम से कार्य करती है। इस हेतु संवैधानिक प्रावधान भी नियत हैं।भारतीय संविधान अनुच्छेद 15, 16, 46 और 335 के तहत एससी/एसटी/ओबीसी को शिक्षा, नौकरियों और विधायी सुरक्षा प्रदान करता है, जो भेदभाव रोकने और उत्थान सुनिश्चित करने के लिए हैं। वहीं, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करता है। जबकि एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अपराधों पर दंड और पीड़ितों को राहत देता है।

आरक्षण सम्बन्धी प्रमुख नीतियां भी स्पष्ट हैं। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण एससी को 15 प्रतिशत, एसटी को 7.5 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत कोटा नियत है। इसी आधार पर उन्हें छात्रवृत्तियां भी दी जाती हैं। उन्हें पोस्ट-मैट्रिक, प्री-मैट्रिक और अन्य योजनाएं वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं। वहीं, कल्याणकारी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, स्वरोजगार ऋण, कौशल विकास और आवास योजनाएं (जैसे अंबेडकर आवास योजना) से भी उन्हें लाभान्वित किया जाता है। वहीं, नजरिए से भी ये नीतियां दक्षिण अफ्रीका या अमेरिका जैसे देशों की क्षतिपूर्ति से भिन्न हैं, जहां प्रत्यक्ष आर्थिक मुआवजा दिया जाता है; जबकि भारत में फोकस सशक्तिकरण पर है, लेकिन इसके दुरुपयोग और सामाजिक तनाव की अकसर आलोचना होती है। सवाल है कि आखिर ऐतिहासिक भेदभाव या उत्पीड़न क्या है? तो जवाब होगा कि ऐसे ऐतिहासिक भेदभाव या उत्पीड़न से तात्पर्य उन सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक प्रक्रियाओं से है जो लंबे समय से चली आ रही हैं और जिनके कारण कुछ समूहों को व्यवस्थित रूप से हाशिए पर धकेल दिया गया। यह अक्सर जाति, नस्ल, लिंग या धर्म जैसे आधारों पर आधारित होता है, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी सामाजिक संरचनाओं में निहित हैं। वहीं, उत्पीड़न इसके हिंसक या शोषणकारी रूप को दर्शाता है, जैसे बहिष्कार या हिंसा। इस प्रकार ऐतिहासिक भेदभाव किसी विशिष्ट विशेषता (जैसे जाति या नस्ल) के आधार पर समूहों के साथ जानबूझकर भिन्न व्यवहार है, जो पीढ़ियों तक चलता रहता है। भारत में यह जाति व्यवस्था से जुड़ा है, जहां दलितों को मंदिर, पानी या शिक्षा से वंचित रखा गया था। भारत में इसके लिये अकसर सवर्ण समाज खासकर ब्राह्मणों को आरोपित किया जाता है, जबकि सनातनी ब्राह्मणों ने तो उन्हें धार्मिक रूप से भी हिंदुत्व की माला में पिरोया है और उन्हें श्रेष्ठता प्रदान की है। जबकि मुस्लिम काल और अंग्रेजी काल में उनके हुए उत्पीड़न व शोषण से इनकार नहीं किया जा सकता है। चूंकि भारत सरकार में भी इस्लामिक व ब्रिटिश सत्तागत सोच वाली बुराइयों को निरंतरता प्रदान की गई है, जो बहस का विषय है। उदाहरणस्वरूप, जातीय उत्पीड़न को ही लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि दलितों पर शारीरिक हिंसा, यौन शोषण या सामाजिक बहिष्कार, जो औपनिवेशिक काल से चला आ रहा, निंदनीय है। वहीं, नस्लीय भेदभाव का भी यही आलम है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति या अमेरिका में रेडलाइनिंग, जहां नस्ल के आधार पर ऋण अस्वीकार किए गए। कुछ वैसा ही घटनाक्रम भारत में भी चला ब्रिटिश प्रभाव वश। वहीं, उपनिवेशिक प्रभाववश मुगलिया और ब्रिटिश राज में भारतीय अभिजात वर्ग को भी भेदभाव का शिकार बनाया गया, जो सामाजिक विषमता को गहरा करने वाला था। यह भेदभाव आज भी असमानता को बनाए रखता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा या रोजगार में अवसरों की कमी। कानूनी उपाय जैसे भारत का संविधान (अनुच्छेद 15, 17) इसे समाप्त करने का प्रयास करते हैं। भारत में भेदभाव रोकने के लिए संविधान और विभिन्न कानून प्रमुख भूमिका निभाते हैं, खासकर जाति, नस्ल या लिंग आधारित ऐतिहासिक भेदभाव के खिलाफ। ये प्रावधान समानता सुनिश्चित करते हैं और दंडनीय अपराध बनाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार देते हैं। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 धर्म-जाति-लिंग आदि पर भेदभाव निषेध, अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता उन्मूलन, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत सुनिश्चित करते हैं। वहीं, कुछ प्रमुख कानून भी बनाए गए हैं। जैसे नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955~ अस्पृश्यता या छुआछूत को दंडनीय बनाता है। एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989~ अनुसूचित जाति/जनजाति पर अत्याचार रोकने के लिए सख्त प्रावधान। इसी सिलसिले की अगली कड़ी ष्ट विनियम, 2026 है, जिससे उच्च शिक्षा में जाति-आधारित भेदभाव रोकने के नए नियम बनाये गए हैं। जहां तक इनके कार्यान्वयन की बात है तो ये कानून अदालतों द्वारा लागू होते हैं, जैसे इंद्रा साहनी मामले में आरक्षण को मान्यता। शिकायत के लिए समर्पित सेल और पोर्टल उपलब्ध हैं। यूजीसी बिल पर भी सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश विचारणीय है। (लेखक वरिष्ठ पत्रकार व राजनीतिक विश्लेषक है)। (इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

गांव-गांव घूमकर भारत को समझते रहे मार्क टली

(राजेश प्रियदर्शी)

भारत में बीबीसी की पहचान रहे सर मार्क टली का जाना दुखद है। बीबीसी परिवार के लिए तो मानो पितामह के गुजर जाने जैसा है। मेरी खुशकिस्मती है कि उनसे कई बार मिलने और बातें करने का अवसर मिला, लेकिन हमसे पहले वाली पीढ़ी ज्यादा खुशकिस्मत थी, जिसने उनको और ज्यादा करीब से, उनकी सक्रियता वाले दौर में देखा।

मार्क टली पिछले कुछ समय से बीमार चल रहे थे, लेकिन कुछ महीनों पहले तक हिन्दुस्तान टाइम्स में उनका कॉलम देखकर यह आश्वस्ति होती थी कि वह ठीक हैं। उनसे सीखने लायक अनेक बातों में से एक बात तो यही थी कि मार्क टली हर किसी से, हर समय सीखते रहते थे। भारत के समाज और राजनीति की उनकी समझ बहुत गहरी थी, लेकिन वह अक्सर अपने वाक्य की शुरुआत कुछ यूं करते, 'मुझे तो ज्यादा मालूम नहीं, आप बताइए कि...।' जिन बातों की उन्हें पक्की जानकारी होती थी, उनके बारे में भी वह यही कहते थे, 'जहां तक मुझे मालूम है...।'

मुझसे कई बार वह झारखंड के बारे में पूछते थे। मार्क टली से बात करते हुए डर कभी नहीं लगा, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ज्ञान के आतंक की जगह विनम्र विद्वता की आभा थी, लेकिन इस बात का एहसास मुझे हमेशा रहता था कि वह संथालों और मुंडाओं के बारे में उतना ही जानते थे, जितना उत्तर प्रदेश के निषादों और बिहार के मुसहरों के बारे में या फिर केरल के पानियन या मुथुवन लोगों के बारे में। उनकी किताब नो फुल स्टॉप इन इंडिया हर उस व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, जो भारत को गहरे समझना चाहता है। वह सबसे पहले अच्छी तरह यही समझाते हैं कि भारत समझ में क्यों नहीं आता? टली ने एक ब्रितानी अर्थशास्त्री के हवाले से कहीं लिखा था- 'भारत के बारे में जो आप सच कह सकते हैं, उसके ठीक विपरीत बात भी सच होती है।'

तकरीबन 90 साल पहले ब्रिटिश शासन के दौरान जन्मे मार्क टली हर तरह से एक खांटी हिन्दुस्तानी थे। ज्यादातर समय खादी के कुरते और सैंडल पहनने वाले टली साहब लंबे समय तक दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में रहे और धूप में घूमते रहने के कारण उनका गोरा रंग एक उम्र के बाद लगभग तांबई हो गया था। कोई अनजान आदमी उन्हें देखकर एकबारगी यह नहीं कह सकता था कि वह अंग्रेज हैं।

कई दशकों तक भारत और दक्षिण एशिया की ऐतिहासिक घटनाओं पर शानदार पत्रकारिता करने वाले मार्क टली को आपातकाल के दौरान उनकी रिपोर्टिंग के कारण कुछ समय के लिए यहां से निकाल दिया गया था। वह लगातार निडर, लेकिन संतुलित पत्रकारिता करते रहे। मेरे बीबीसी पहुंचने से तीन साल पहले ही1994 में उन्होंने इस संस्थान से इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह लगातार सक्रिय बने रहे। मार्क टली ने कोई दस किताबें लिखी हैं, जो बहुत ही दिलचस्प और पठनीय हैं।

मेरी उनसे पहली लंबी बातचीत सन् 2001 के कुंभ मेले के दौरान हुई थी। तब उन्होंने बहुत विस्तार और गहराई से समझाया कि विदेशी लोग कुंभ मेले में क्यों खिंचे चले आते हैं? किसी भी विषय पर मार्क टली से बात करने का मतलब समझ की एक नई खिड़की का खुलना होता था। उन्होंने भारत को गांव-गांव घूमकर समझा था। वह हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहना चाहते थे, जो उनको 'फर्स्ट हैंड' जानकारी दें। वह दिल्ली में संपादकों और बड़े पत्रकारों से जानकारी लेने में कम ही यकीन रखते थे। एक और बात, जो उन्हें विलक्षण बनाती थी, वह थी सहृदयता। मैंने कभी मार्क टली के मन में किसी के प्रति कटुता या दुराव का भाव नहीं देखा। उनको पसंद करने वालों की संख्या लाखों में थी, क्योंकि उन्हें नापसंद करने का कोई वास्तविक कारण खोजना मुश्किल काम था। मार्क टली को जैसी लोकप्रियता और प्रतिष्ठा मिली, वह शायद ही किसी और पत्रकार को नसीब हो, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने व्यक्तित्व को सेलिब्रिटी होने की सहज संभावना से दूर रखा। मार्क टली से हर मुलाकात के बाद यह विस्मय रह जाता था कि वह इतने अद्भुत कैसे हैं? एक ऋषि जैसा जीवन जीकर विदा हुए सर मार्क टली को श्रद्धांजलि! (लेखक वरिष्ठ संपादक, बीबीसी हैं) (ये लेखक के अपने विचार हैं)

सांसद निधि की तुलना दूसरी योजनाओं से नहीं हो सकती

सांसद स्थानीय विकास निधि को लेकर इन दिनों एक वितंडा खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले दिनों कुछ सांसदों के बारे में दावा किया गया कि उन्होंने इस मद का एक रुपया भी खर्च नहीं किया। इसी आधार पर कई लोग दलील दे रहे हैं कि इस योजना को ही खत्म कर देना जाना चाहिए, मगर सच यह है कि इसकी ऐसी उपयोगिता है, जिसकी विकास की अन्य योजना निधियों से तुलना नहीं की जा सकती। इसे व्यापक संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इसका कारण है। देश की आधारभूत संरचनाओं में प्रगति अब ठोस यथार्थ बन चुकी है। सड़क, पानी, बिजली, नाली, सीवर आदि जो कल तक स्थानीय लोगों की ज्वलंत समस्याएं हुआ करती थीं और लोग उसके समाधान की अपेक्षा सांसद-विधायक विकास निधि से रखते थे, वह बात अब प्रायः नहीं रही। पंचायत से लेकर जिले तक का बजट पिछले दस वर्षों में कई गुना बढ़ा है।

(राकेश सिन्हा)

यहां एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है। दुनिया के सभी पदों के पास घोषित शक्तियां होती हैं और पद के अनुपात में उनका विशेषाधिकार रहता है, परंतु सांसद के पास शक्ति शून्य है। वह जनता की वैधानिक ताकत से प्रतिनिधि बनता है, जनता के जीवन के सभी आयामों से उसका सरोकार होता है। अतः सांसद की ताकत विशेषाधिकार के गर्भ से उपजता है। सांसद निधि इसी विशेषधिकार को रेखांकित करता है।

इसके उपयोग में जितनी प्रयोगधर्मिता होगी, परिणाम उतने ही प्रभावी होंगे। एक उदाहरण देना चाहूंगा। बिहार के बेगूसराय के एक छोटे-से मुहल्ले (टोला) में सामाजिक-आर्थिक रूप से हाशिये के लोग रहते हैं। युवाओं से संवाद में पुस्तकालय-निर्माण की मांग उठी। इसकी घोषणा करके राशि आवंटित कर देना एक मिनट का काम था। मैंने ऐसा नहीं किया। घंटों अनौपचारिक संवाद चलता रहा। उसी सिलसिले में टोले का जातिसूचक नाम बदलने पर राय बनी। नया नाम तय हुआ-हनुमान-शिव टोला। मैंने पाया है कि ग्रामीण क्षेत्रों

में पुस्तकालयों के प्रति आकर्षण है। एक पुस्तकालय पीढ़ियों की सोच के निर्माण का पवित्र स्थल है, जहां अध्ययन, चिंतन, सृजन और संकल्प निर्माण होता है। पुस्तकालय भौतिकता, अनैतिकता, संकीर्णता आदि से उत्पन्न आपदाओं से समाज को बचाता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से सत्ता संभाली है, खेल के प्रति उन्होंने युवाओं में उत्साह बढ़ाया है। खेल में भी सुनहरा करियर है, गांव-कस्बों तक यह संदेश गया है। अतः खेल-सुविधाओं की भी मांग अब सांसदों से होने लगी है। चाहे निर्माण या विकास का रूप जो भी हो, इसमें बहुआयामी संवाद का जरिया बनने की असीम क्षमता है। सांसद निधि के साथ नैतिकता का आयाम लगते ही उसकी व्यापकता बढ़ जाती है। एक तरफ, निर्माण कार्य होता है, दूसरी तरफ संकीर्णता की दीवार ढहने लगती है। सूची बनाकर विकास योजनाओं को जारी करना या मांग के आधार पर आवंटन की अपनी उपयोगिता है, पर वे जिलाधिकारी की योजना की तरह हो जाती हैं। उससे सांसद निधि का सामाजिक-सांस्कृतिक पक्ष अंकुरित भी नहीं हो पाता है।

मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स में कोंगथोंग गांव को मैंने 2020 में गोद लिया था। सेंगखासी (जनजाति) का स्कूल सरकारी सहायता से वंचित था। सहायता देने से पूर्व लोगों के सामूहिक श्रमदान, स्वच्छता अभियान आदि पर संवाद होते रहे। ऐसे में, सांसद निधि स्कूल के विकास से अधिक वहां सामूहिकता के भाव को आगे बढ़ाने का माध्यम बन गई। श्रमदान द्वारा निधि का उपयोग हुआ। सुखद बात यह रही कि ईसाई और सेंगखासी समुदायों के बीच चली आ रही कटुता मिट गई।

हमारे लोकतंत्र में एक कमी है, सांसदों के कार्यकलापों, विशेषकर सांसद निधि के उपयोग का सोशल ऑडिटिंग न होना। यह 'सब धान बाईस पसेरी' कर देता है। सोशल ऑडिटिंग से उनकी कमियों पर प्रभावी अंकुश लग सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ जनादेश नहीं है। इसकी बुनियाद में नैतिक व्यवस्था है। इसलिए सांसद निधि का उपयोग रचनात्मक तरीके से होना चाहिए। (लेखक पूर्व सदस्य, राज्यसभा) (ये लेखक के अपने विचार हैं)

सड़क पर दिखा मलाइका का बोल्ड अवतार

मलाइका अरोरा 52 साल की उम्र में भी अपने बोल्ड अवतार से इंटरनेट पर तहलका मचा देती हैं। मलाइका अरोरा हाल ही में मुंबई की सड़कों पर स्पॉट हुईं, इस दौरान उन्होंने अपने रिवीलिंग आउटफिट और अपनी अदाओं से पैपराजी का ध्यान खींच लिया। वायरल वीडियो में मलाइका अरोड़ा ऑल-ब्लैक को-ऑर्ड सेट में नजर आ रही हैं। उन्होंने एक रिवीलिंग डीप-नेक टॉप के साथ ब्लैक लैदर पैंट्स और एक मैचिंग क्रॉप जैकेट कैरी की है। बड़े डार्क सनग्लासेस और हाथों में स्टाइलिश क्लच उनके लुक को और भी ग्लैमरस बना रहा था।

इस दौरान एक्ट्रेस का नया हेयरस्टाइल भी देखने को मिला। मलाइका की डीपनेक ड्रेस ने सभी का ध्यान अपनी और खिंचा। हालांकि भीड़ के बीच वह अपने आउटफिट को एडजस्ट करती दिखाई दीं। मलाइका के चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। पैपराजी को देखते ही उन्होंने ग्रेसफुली पोज दिए, जो उनकी फिटनेस और स्टाइल के प्रति उनके समर्पण को दर्शाता है। मलाइका अरोरा का करियर 90 के दशक में बतौर MTV VJ शुरू हुआ था। उन्हें असली पहचान शाहरुख खान के साथ 'छैय्या-छैय्या' गाने से मिली। इसके बाद उन्होंने मुन्नी बदनाम हुई, अनारकली डिस्को चली और माही वे जैसे गानों से बॉलीवुड में अपनी अलग जगह बनाई।

आयुष्मान खुराना की
'पति पत्नी और वो दो' के लिए करना होगा और इंतजार

आयुष्मान खुराना आखिरी बार हॉरर कॉमेडी 'थामा' (2025) में नजर आए थे। इसके बाद एक्टर जल्द ही 'पति पत्नी और वो' के सीक्वल में नजर आने वाले हैं। बीते साल फिल्म की अनाउंसमेंट हुई, जिसके बाद से ही इस सीक्वल का फैंस से बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस सीक्वल का टाइटल रखा गया है 'पति पत्नी और वो दो'। आयुष्मान खुराना के अलावा इसमें सारा अली खान भी नजर आने वाली हैं। मेकर्स ने कुछ वक्त पहले इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी थी।

'पति पत्नी और वो दो' पहले होली पर रिलीज होने वाली थी। लेकिन अब मेकर्स ने इसकी रिलीज के प्लान में बदलाव किया है। 'पति पत्नी और वो' साल 2019 में रिलीज हुई थी, जो बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। मुदस्सर अजीज के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म का सीक्वल भी वही डायरेक्ट करेंगे। 'पति पत्नी और वो दो' 4 मार्च को रिलीज होने वाली थी, जिसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी हो गई थी। हालांकि, अब मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट बदलने का फैसला लिया है। बॉलीवुड हंगामा ने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्स के हवाले से बताया कि 'पति पत्नी और वो दो' प्लान के मुताबिक 4 मार्च को सिनेमाघरों में नहीं आएगी। ऐसा इसलिए, क्योंकि पोस्ट-प्रोडक्शन अभी पूरा नहीं हुआ है और एक गाना भी शूट होना बाकी है। मेकर्स इस प्रोसेस में जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। वो इस बात का खास ध्यान रखना चाहते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट ऑडियंस के लिए एंटरटेनिंग हो। इसी वजह से मेकर्स ने इस सीक्वल की रिलीज को टालने का फैसला किया है। नई रिलीज डेट जल्द ही अनाउंस होने की उम्मीद है।

आलिया भट्ट और राजकुमार राव की पहली बार बनेगी जोड़ी

आलिया भट्ट इन दिनों एक्शन फिल्म अल्फा और पीरियड रोमांस लव एंड वार को लेकर चर्चा में हैं। अब खबर है कि एक्ट्रेस जल्द ही हाउसवाइफ का हिस्सा भी होंगी। यह एक रिश्तों पर आधारित ड्रामा फिल्म है और इसे 'दृश्यम 2' के निर्देशक अभिषेक पाठक प्रोड्यूस कर रहे हैं। Variety India की रिपोर्ट के अनुसार, आलिया भट्ट फिल्म में हाउसवाइफ का किरदार निभाएंगी। फिल्म में लीड एक्टर के तौर पर राजकुमार राव से बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। रिपोर्ट के अनुसार, आलिया भट्ट केवल मुख्य भूमिका निभाएंगी ही नहीं, बल्कि अपनी प्रोडक्शन कंपनी, एटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस के तहत इस फिल्म की को-प्रोड्यूसर भी होंगी। वह इस प्रोजेक्ट में अभिषेक पाठक की पैनोरमा स्टूडियोज के साथ भी सहयोग करेंगी।

फिल्म की शूटिंग इस साल अगस्त-सितंबर में शुरू होने की संभावना है। यह प्रोजेक्ट तब शुरू होगा जब अभिषेक पाठक अपनी नई फिल्म 'दृश्यम 3' की शूटिंग पूरी कर लेंगे।

इसके अलावा आलिया भट्ट 2027 के लिए कई अन्य प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत कर रही हैं, जिनमें मैडॉक फिल्म्स की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'चामुंडा' भी शामिल है। आलिया की अगली फिल्म 'अल्फा' होगी, जो शिव रावल के निर्देशन में बनने वाला एक हाई-ऑक्टेन एक्शन थ्रिलर है। इस फिल्म में वह एलिट ऑल-वुमेन कॉम्बैट यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर का किरदार निभाएंगी, जिसमें उनके साथ शर्वरी वाघ भी हैं। यह फिल्म YRF स्पाय यूनिवर्स में सेट की गई है और इसमें बॉबी देओल भी अहम भूमिका में होंगे। यह फिल्म कब रिलीज होगी इसको लेकर अब तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है।

आलिया भट्ट को फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वार' में रणबीर कपूर और विक्की कौशल के साथ भी देखा जाएगा। उन्हें आखिरी बार वासन बाला की 'जिगरा' में अभिनेता वेदांग रैना के साथ स्क्रीन पर देखा गया था।

राजकुमार और आलिया की अगली फिल्में

इसके अलावा गौर किया जाए राजकुमार राव और आलिया भट्ट की अन्य फिल्मों की तरफ तो आने वाले समय में अभिनेता राजकुमार ओटीटी फिल्म टोस्टर में नजर आएंगे, जिसका एलान मंगलवार को नेटफ्लिक्स की तरफ से कर दिया गया है। इसके अलावा आलिया भट्ट निर्देशक संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर में दिखाई देंगी।

'वध 2' की एडवांस बुकिंग शुरू

2026 की सबसे मोस्ट-अवेटेड थ्रिलर मिस्ट्री फिल्मों में शामिल 'वध 2' एक बार फिर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता जैसे अनुभवी और सम्मानित कलाकारों को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है। रिलीज डेट करीब आते ही दोनों कलाकारों ने दर्शकों से अपील की है कि वे वध 2 को सिनेमाघरों में जरूर देखें। 6 फरवरी, 2026 को रिलीज़ होने वाली इस फिल्म की एडवांस बुकिंग अब शुरू हो चुकी है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही यह फिल्म दर्शकों को लगातार इंट्रीग कर रही है और लोग इसकी रिलीज़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जसपाल सिंह संधू द्वारा लिखी और निर्देशित, और लव रंजन व अंकुर गर्ग की लव फिल्म्स के बैनर तले बनी यह स्पिरिचुअल सीक्वल 2026 की सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली और मोस्ट-अवेटेड रिलीज़ में शामिल हो चुकी है। 2025 में 56वें IFFI में हुई इसकी गाला प्रीमियर के बाद फिल्म को लेकर उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया, जहां इसे जोरदार तालियां मिलीं और एक बार फिर संजय मिश्रा और नीना गुप्ता की भारतीय सिनेमा के सच्चे दिग्गजों के रूप में पहचान पुख्ता हो गई।

5 साल बाद रिया चक्रवर्ती की एक्टिंग में वापसी

सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद लंबे समय तक ब्रेक लेने के बाद रिया चक्रवर्ती फिर से फिल्मों और सीरीज में वापसी कर रही हैं। मंगलवार शाम वह मुंबई में हुए 'Next On Netflix' इवेंट में शामिल हुईं, जहां एक्ट्रेस ने अपनी कमबैक सीरीज फैमिली बिजनेस की आधिकारिक घोषणा की। इस सीरीज में रिया के साथ अनिल कपूर और विजय वर्मा भी नजर आएंगे।

रिया चक्रवर्ती ने अपने इंस्टाग्राम पर फैमिली बिजनेस का टीजर शेयर किया। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, नई शक्ति मिलती है पुराने पैसे से। जब सत्ता बड़ी होती है, तो परिवार और कारोबार की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। फैमिली बिजनेस जल्द ही केवल नेटफ्लिक्स पर देखें। रिया के कमबैक से उनके फैंस काफी खुश हैं। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस को सपोर्ट किया जा रहा है। एक फैन ने लिखा, देर आए, दुरुस्त आए, बधाई। दूसरे ने कहा, रिया को स्क्रीन पर वापस देख खुश हूं। यह वापसी उनके लिए पूरी तरह न्यायसंगत है, इंतजार नहीं कर सकता इसे देखने का। इसके अलावा कई और यूजर्स ने खुशी जताई है। बता दें, 2020 में सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया था। उसी साल सितंबर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने रिया चक्रवर्ती को हिरासत में लिया, जब उनके व्हाट्सएप से कथित ड्रग्स से जुड़े चैट्स सामने आए। अगले महीने उन्हें जमानत दे दी गई थी। इस शर्त के साथ कि वह अपना पासपोर्ट एनसीबी के पास जमा करें। हालांकि रिया को पांच साल बाद उनका पासपोर्ट वापस मिल गया है। यह पासपोर्ट उन्हें तब मिला जब हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया था।

अनिल कपूर ने 26 साल पुरानी फिल्म को लेकर किया पोस्ट, इस बात पर फैन हुआ नाराज

साल 2000 में रिलीज हुई राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म 'पुकार' में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित नजर आए थे। फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस ने पसंद किया था। इस फिल्म को हाल ही में 26 साल पूरे हुए। ऐसे में एक्टर ने एक पोस्ट की, जिसमें फिल्म 'पुकार' का गाना 'सुनता है मेरा खुदा' शेयर किया। साथ ही लिखा, 'पुकार फिल्म का मेरा फेवरेट गाना, आज में इसे रिपीट पर सुनने वाला हूं।' इस गाने को शेयर करते हुए वह ऐसी गलती कर बैठे, जिस पर एक फैन नाराज हो गया। जानिए, क्या है पूरा मामला?

दो खास लोगों के नाम भूल गए अनिल कपूर

फिल्म 'पुकार' के गाने 'सुनता है मेरा खुदा' को साझा करते हुए अनिल कपूर ने फिल्म से जुड़ी टीम का भी जिक्र किया। लेकिन उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति का नाम लिखना भूल गए। इन दोनों सिंगर्स ने पुकारा फिल्म का गाना 'सुनता है मेरा खुदा' गाया था। फैन ने अनिल कपूर को यह बात याद दिलाते हुए ट्वीट किया और लिखा, 'यह शर्म की बात है सर कि आपने अपने ट्वीट में सिंगर उदित नारायण सर और कविता मैडम को छोड़कर बाकी सबका जिक्र किया है। ऐसा लगता है कि बॉलीवुड में 90 के दशक के सिंगर्स के साथ दूसरे दर्जे के नागरिकों जैसा बर्ताव किया जाता है।'

मनोज बाजपेयी की फिल्म 'घूसखोर पंडत' पर विवाद

मनोज बाजपेयी इन दिनों अपनी नई फिल्म घूसखोर पंडत को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में एक इवेंट में फिल्म का टीजर जारी किया गया, जिसके बाद यह विवादों में घिर गया। मुंबई के एक वकील का आरोप है कि 'पंडित' जैसे सम्मानजनक शब्द को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस कारण उन्होंने फिल्म के मेकर्स को कानूनी नोटिस भेजा है। रिपोर्ट के मुताबिक, यह नोटिस मुंबई के वकील आशुतोष दुबे ने भेजा है। उनका आरोप है कि 'पंडित' जैसे सम्मानजनक शब्द को भ्रष्टाचार के साथ जोड़ना न केवल गैर-जिम्मेदाराना है, बल्कि इससे पूरे समुदाय की गरिमा को ठेस पहुंचती है। नोटिस में कहा गया है कि यह फिल्म जानबूझकर एक समुदाय की छवि को खराब करने की कोशिश कर रही है। वकील ने आगे यह भी कहा कि नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी इस तरह के कंटेंट को प्रमोट कर रही है। 'पंडित' शब्द भारतीय सभ्यता में नैतिकता और आध्यात्मिक अधिकार का प्रतीक है। इसे रिश्वतखोरी और अपराध के साथ जोड़कर दिखाना गलता है। यह केवल क्रिएटिव फ्रीडम नहीं है बल्कि कला के नाम पर किसी समुदाय की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना है। उनका कहना है कि फिल्म का नाम केवल सनसनी फैलाने के इरादे से रखा गया है, जिसमें सामाजिक संवेदनशीलता की अनदेखी की गई है। इसके साथ ही, वकील ने फिल्म का नाम बदलने की मांग भी की है।

दिशा पाटनी संग रिश्ते की खबरों पर तलविंदर का रिएक्शन

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी और पंजाबी सिंगर तलविंदर इन दिनों अपने कथित रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में हैं। दोनों को मुंबई में हुए एक कॉन्सर्ट में हाथ में हाथ डाले देखा गया था, जिसके बाद उनके डेटिंग की खबरें आने लगीं। अब इन खबरों पर तलविंदर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

एक इंटरव्यू में तलविंदर ने कहा, हमारी मुलाकात शादी से ठीक पहले हुई थी और अचानक मिली इतनी सारी चर्चा ने हमें हैरान कर दिया। हम न तो किसी दबाव में आना चाहते हैं और न ही अफवाहों पर ध्यान देना चाहते हैं। हम अभी खुद को समझने और एक-दूसरे को जानने की प्रक्रिया में हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर लोग अफवाहें फैलाने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें अफवाह ही रहने दूंगा। जब तलविंदर से पूछा गया कि क्या वह प्यार और रिश्तों के बारे में सोचते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं हर दिन प्यार में पड़ जाता हूं। मैं अभी भी प्यार में पड़ रहा हूं। गौरतलब है कि लोलापालूजा इंडिया 2026 म्यूजिक फेस्टिवल में दिशा पाटनी और तलविंदर को एक साथ देखा गया था। दोनों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वे इवेंट के दौरान एक-दूसरे का हाथ पकड़े नजर आए।

धैर्य, संकल्प और साधना से तय होता है सिनेमा का सफर: जाहिद शाह

जाहिद शाह ने अपनी कला यात्रा रंगमंच गुरु रंजीत कपूर के साथ 1990 में रंगमंच से शुरू की, उनकी पहली सिद्धार्थ बासु निर्देशित टेलीफिल्म 'कव्वा चला हंस की चाल' दूरदर्शन पर प्रसारित हुई, जिसमें इन्होंने एक टेलर मास्टर का रोल किया था, अभिनय के साथ साथ इन्होंने लेखन और निर्देशन में भी कदम रखा, जिसके अंतर्गत इनके द्वारा निर्देशित सीरियल टप टप टोपी टोपी 1996 में बहुत लोकप्रिय हुआ, इनकी रचनात्मक कलात्मक प्रतिभा को पहचानते हुए सन 2002 में अभिनय सम्राट स्वर्गीय दिलीप कुमार और सायरा बानो जी ने इनको अपने टीवी सीरियल 'अल्लाह मेरी तौबा' से पहला ब्रेक दिया उसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यह ज़ी सलाम से बतौर निर्माता 10 साल जुड़े रहे इनके द्वारा लिखित निर्देशित बहुत सी वेब सीरीज विभिन्न ओटीटी प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं इनमें सबसे प्रमुख वाचो डिश टीवी की वेब सीरीज जौनपुर है, जिसमें इन्होंने एक भ्रष्ट पॉलिटिशियन का रोल किया और उसके लिए 2023 में हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यन्त चौटाला ने इनको बेस्ट नेगेटिव रोल के सम्मान से सम्मानित किया। आजकल इनका दीपक तुलसी रामसे द्वारा निर्देशित टीवी सीरियल रामसे हाउस दूरदर्शन नेशनल पर रविवार को प्रसारित हो रहा है। आज 6 फरवरी को इनकी फिल्म श्चक्कर चवन्नी कार समस्त भारत में प्रदर्शित हो रही है जिसमें वह जबरदस्त कॉमेडी करते नज़र आएंगे।

जीसीसी क्लब एवं होटल में फिल्मी हस्तियों का जमावड़ा

मीरा रोड स्थित जीसीसी क्लब एवं होटल में बेटी के जन्म की खुशी में सोनू कुमार झा ने अपनी पूरे परिवार के साथ एक भव्य पार्टी का आयोजन किया, जहां सोनू कुमार झा को बधाई देने के फिल्म निर्माता सोहेल मकलई (कंगना रनौत अभिनीत फिल्म धाकड़), फिल्म निर्देशक अमन अरोरा, अभिनेता क्षितिज सिंह, अभिनेत्री संगीता तिवारी, नगरसेवक विवेक उपाध्याय की उपस्थित रही। साथ ही सांस्कृतिक कलाकार और पेशेवर डांसर्स की उपस्थिति रही। आयोजन की व्यवस्था, प्रस्तुति और अनुशासन की सभी ओर सराहना हुई। झा परिवार में नन्ही कन्या के जन्म को केवल पारिवारिक खुशी नहीं, बल्कि आस्था, सनातन परंपरा और आध्यात्मिक अनुभूति से जुड़ा एक विशेष क्षण माना जा रहा है। बच्ची के पिता सोनू कुमार झा, जो स्वयं महादेव के अनन्य भक्त और सनातन परंपरा में आस्था रखने वाले हैं,

इस पूरे घटनाक्रम को ईश्वर की विशेष कृपा के रूप में देख रहे हैं। सोनू कुमार झा के अनुसार, उनकी धर्मपत्नी एकता झा के नौ माह पूर्ण होते ही परिवार में एक अलग ही उत्साह का वातावरण बन गया था। इसी दौरान गुप्त नवरात्रि चल रही थी और नवरात्रि के तीसरे दिन कन्या का जन्म हुआ। यह संयोग उनके लिए अत्यंत भावनात्मक और आध्यात्मिक रहा।

महाशिवरात्रि का त्योहार कब मनाया जाएगा? 15 या 16 फरवरी

साल 2026 में महाशिवरात्रि का महापर्व 15 फरवरी 2026, रविवार को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। चूँकि मुख्य पूजा मध्यरात्रि (निशीथ काल) में होती है, इसलिए 15 फरवरी की रात ही शिव साधना के लिए सबसे उत्तम है।

● महाशिवरात्रि 2026: शुभ मुहूर्त:-

चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 15 फरवरी 2026, शाम 05:04 बजे से।
चतुर्दशी तिथि समाप्त: 16 फरवरी 2026, शाम 05:34 बजे तक।

● दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त:-

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:13 से 12:58 तक।
गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:09 से 06:34 तक।

● निशीथ काल (मुख्य पूजा) समय:-

15 फरवरी की रात 11:52 PM से 16 फरवरी की रात 12:42 AM तक। स्थानीय समय में 5-7 मिनट का अंतर रहता है।
पारण का समय: 16 फरवरी को सुबह 06:59 बजे के बाद।

● विशेष नोट:-

चूंकि शिवरात्रि का पर्व रात्रि में मनाया जाता और इसकी पूजा निशीथ कल में होती है। इसलिए कई विद्वान 15 फरवरी को मनाया जाने की सलाह दे रहे हैं। काल निर्णय और लाल रामस्वरूप कैलेंडर में 15 फरवरी की तारीख दी गई है।

● रात्रि के चार प्रहर की पूजा का समय

शिवरात्रि पर रात भर जागकर चार प्रहर की पूजा करने का विधान है, जिसके समय इस प्रकार रहेंगे:

प्रथम प्रहर: शाम 06:11 PM से रात 09:23 PM तक।
द्वितीय प्रहर: रात 09:23 PM से रात 12:35 AM तक।
तृतीय प्रहर: रात 12:35 AM से सुबह 03:47 AM तक।
चतुर्थ प्रहर: सुबह 03:47 AM से सुबह 06:59 AM तक।

ऑनलाइन गेम की आदत बच्चों की ले रही है जान

मेंटल हेल्थ बिगाड़ रहा रील्स का एडिक्शन

एक गेम, एक टास्क और सेकंड में पूरा परिवार तबाह। आज का दौर मोबाइल फ़ोन का दौर है, लेकिन हंसते-खेलते बच्चे स्क्रीन में इस कदर डूब रहे हैं कि मां-बाप को पता भी नहीं चलता और जिंदगी हाथ से फिसल जाती है। जी हां गाजियाबाद के दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को हिला दिया है। 3 फरवरी की रात तीन सगी बहनों ने 9वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। बच्चियों की उम्र 16 साल, 14 साल और सिर्फ 12 साल की थी। जो मोबाइल गेम 'कोरियन लवर' की आदी थीं। गेम के आखिरी टास्क के नाम पर बच्चियों ने आत्महत्या कर ली। घर में माता-पिता थे, लेकिन बच्चों की दुनिया बस मोबाइल बन चुका था।

पुलिस को मिला सुसाइड नोट दिल दहला देने वाला था। मोबाइल बच्चों की जिंदगी बन गया था। बच्चियां तीन साल से गेम की गिरफ्त में थी मां-बाप को खबर ही नहीं लगी और परिवार बर्बाद हो गया। ये अकेली घटना नहीं है। कर्नाटक में एक 13 साल का बच्चा छत से कूद गया, जबकि मां घर के अंदर थी। बच्चा मोबाइल गेम के चैलेंज के चक्कर में था। मतलब मोबाइल गेम्स अब सिर्फ मनोरंजन नहीं जानलेवा बन चुके हैं। अब दिमाग में सवाल आता है कि ये मोबाइल गेम्स आखिर बच्चों के दिमाग के साथ कैसे खेलते हैं?

बढ़ रही हैं ये बीमारी

बच्चों के लिए जानलेवा गेम

असल में भारत में इस वक्त करीब '59 करोड़ गेमर्स' हैं। करीब 74% Gen Z हर हफ्ते 6 घंटे से ज्यादा गेम खेलते हैं। डॉक्टर्स के पास हर हफ्ते '4 से 5 केस सिर्फ गेमिंग एडिक्शन' के आ रहे हैं। कर्नाटक में तो कुछ महीनों के अंदर सुसाइड के 32 केस आए, जो सीधे-सीधे ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े थे।

गेम से बच्चों के दिमाग पर असर

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक गेम जीतने पर दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है और यही खुशी धीरे-धीरे एडिक्शन बन जाती है। हार हुई तो गुस्सा, चिड़चिड़ापन, नींद खराब, पढ़ाई खत्म, रिश्ते टूटने लगते हैं। 2026 की एक स्टडी के मुताबिक हाल ये है कि भारत में 60% मानसिक बीमारियां 35 साल से कम उम्र में शुरू हो रही हैं और इसकी बड़ी वजह मोबाइल, स्क्रीन और ऑनलाइन गेमिंग का नशा है। दरअसल, आज जरूरत सिर्फ रोक-टोक की नहीं है। बात समझने की है और बात करने की है। पेरेंट्स को बच्चों के दिल और दिमाग को पढ़ना होगा। वरना गेम के एक छोटे से टास्क के नाम पर बच्चों की जिंदगी यूं ही खत्म होती रहेंगी।

सोशल मीडिया के नुकसान

घबराहट, अकेलापन, अनिद्रा, डिप्रेशन, हकीकत से दूरी, डिजिटल एडिक्शन, TEXT NECK सिंड्रोम का असर, सिरदर्द, गर्दन में अकड़न, झुनझुनी और पीठ दर्द

बीमारी की गिरफ्त में 14 से 24 साल के युवा

पिछले एक साल में 15 से 20% मामले बढ़े, युवा 24 घंटे में से 5-6 घंटे सेलफोन पर रहते हैं, MNC's वाले 8 घंटे लैपटॉप, 5-6 घंटे मोबाइल पर, 20% पढ़ाई करने वाले मोबाइल पर रहते हैं

ब्लाउज या सूट के हुक में जंग से ऐसे रखें सेफ

अक्सर ऐसा होता है कि ब्लाउज ज्यादा पुराने नहीं होते, फिर भी उनके हुक में जंग लग जाता है। मेटल वाले ये हुक ब्लाउज के अलावा सूट, ब्रा या किसी भी आउटफिट में लगे हो सकते हैं। जंग लगने के बाद ये देखने में तो खराब लगते ही हैं, साथ ही कपड़े पर दाग भी छोड़ देते हैं। ऐसा आमतौर पर दो वजहों से होता है। पहला, जब ब्लाउज में धोने के बाद नमी बनी हुई हो और उसे फोल्ड कर के रख दिया जाए। दूसरा पसीने की वजह से भी हुक में जंग लग जाता है। ऐसे में अगर आप अपने ब्लाउज को जंग लगने से सेफ रखना चाहती हैं, तो ये सिंपल से हैक ट्राई कर सकती हैं। अगर पहले से ही जंग लग चुका है और कपड़े पर उसके दाग लग गए हैं, तो इन्हें रिमूव कैसे करना है इसका तरीका भी जानते हैं।

जंग के दाग कैसे छुड़ाएं?

अगर कपड़े पर जंग का दाग लग गया है तो इस सिंपल सी ट्रिक से आप उसे साफ कर सकती हैं। इसके लिए दाग वाले हिस्से पर नमक छिड़क दें। ऊपर से अच्छी तरह नींबू निचोड़ें ताकि सारा दाग अच्छी तरह भीग जाए। अब इसे कपड़ों के ब्रश या टूथब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें और फिर धूप में आधा घंटा सूखने के लिए रख दें। इसके बाद कपड़े को वॉश करेंगी तो जंग का दाग पूरी तरह गायब हो जाएगा। हालांकि ध्यान रखें अगर शिफॉन या सिल्क जैसा नाजुक कपड़ा है, तो पहले छोटे से हिस्से पर टेस्ट जरूर कर लें।

इस हैक से ब्लाउज के हुक में नहीं लगेगा जंग

ब्लाउज या किसी भी आउटफिट में अगर हुक लगा हुआ है तो एक सिंपल सा काम कर सकती हैं। इससे जंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको बस ट्रांसपेरेंट नेल पॉलिश लेनी है और सारे हुक पर अप्लाई कर देनी है। हर हुक पर नेल पॉलिश की दो-तीन लेयर अच्छे से लगा दें। ऐसा करने से हुक बिल्कुल नए जैसे रहेगें। हालांकि ध्यान रखें कि कुछ टाइम बाद नेल पॉलिश हट जाती है इसलिए इसे दोबारा अप्लाई करना ना भूलें। नया हुक लगवाने से बेहतर है कि आप ये नेल पॉलिश वाला सिंपल सा हैक ट्राई कर लें।

हुक में लग गया है जंग तो ये काम करें

अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि एक बार अगर ब्लाउज के हुक में जंग लग जाए, तो इसके दाग पूरे में फैल जाते हैं। इसकी वजह से ब्लाउज का कपड़ा फटने का डर भी रहता है। खासतौर से वो साड़ियां जो आप कभी-कभी पहनती हैं, रखे रखे उनमें जंग फैलने का खतरा रहता है। ऐसे में आप सेलो टेप की मदद ले सकती हैं। थोड़ी सी टेप काटें और सारे जंग लगे हुक पर लगा दें। इससे हुक कवर हो जाएंगे और जंग बाकी के कपड़े को खराब नहीं करेगा।

छोटा बेडरूम कैसे सजाएं

छोटा बेडरूम अक्सर लोग ऐसे सामान और डेकोरेटिव आइटम्स से भर लेते हैं कि वह और छोटा दिखने लगता है। हमेशा कमरे में कम चीजें रखनी चाहिए, जिससे स्पेस दिखे और कमरा भी सुंदर लगे। अगर आपका बेडरूम छोटा है, तो उसे सजाने के लिए कुछ आइडिया हम आपको दे रहे हैं। इन्हें अपनाने के बाद आपका रूम बड़ा दिखेगा और सुंदर भी।

इंटीरियर पर दें ध्यान

कमरे में हमेशा हल्के रंग से पुताई करवाएं। ज्यादा चटक या आंखों में चुभने वाले रंग कमरे को छोटा दिखाते हैं। हल्के और शांत दिखने वाले कलर्स से पुताई करवाएं। इंटीरियर थोड़ा उभरा हुआ करवा सकते हैं, जिससे दीवारों का लुक अच्छा लगे।

पेंटिंग्स या फोटो फ्रेम

कमरे की दीवार पर किसी एक साइड ही पेंटिंग या फैमिली फोटो लगाएं। चारों ओर दीवार पर कुछ भी लटकाने से लुक खराब हो जाता है और ये कमरे को छोटा दिखाता है। बेड के ऊपर फैमिली फोटो या कोई सीनरी पेंटिंग लगवाएं।

साइड टेबल

कमर में बेड के साइड में टेबल रखें, जिससे आपकी छोटी-मोटी चीजें टेबल के अलमारियों में रहें। साइड टेबल पर लैंप सजाएं या कोई फ्लॉवर वॉस सजा सकते हैं। इससे रूम को थोड़ा एस्थेटिक लुक मिलेगा।

पर्दे के रंग

कमरे की खिड़कियों और दरवाजों पर पर्दे अच्छे डिजाइन व कलर के लगवाएं। रूम के पेंट के कलर के हिसाब से कन्ट्रास्ट या फिर मैचिंग में पर्दे लगवाएं। पर्दों से भी कमरे का लुक बदल जाएगा।

बेड बॉक्स चुनें

कमरे को बड़ा और स्पेशियस रखना है, तो सामान रखने वाले फर्नीचर चुनें। जैसे बेड बॉक्स, स्लाइडिंग सोफा, छोटी अलमारियां वगैरह। इससे आप सारा सामान बेड के अंदर रख सकते हैं, बाहर कुछ भी बिखरा नहीं दिखेगा।

कालीन वाला लुक

बेड के नीचे हमेशा डार्क कलर की कालीन बिछाएं। इससे कमरे में एंट्री करने पर आपको बेड वाला एरिया लंबा दिखेगा। ये सिर्फ आंखों का धोखा होता है, क्योंकि यहां पर सारा खेल रंग का है। कालीन से रॉयल फील भी मिलेगा।

पिलो गेम

बेड पर सिर्फ 2 नहीं बल्कि छोटे-छोटे कुशन भी रखें। इससे आपको आराम मिलेगा और देखने में ये सुंदर लगता है। इसके अलावा बेड पर बिछी चादर सही ढंग से और ब्लैंकेट हमेशा फोल्ड करके रखें। इससे कमरा साफ दिखता है।

अचार का डिब्बा बैग में रखने के लिए लें लीक प्रूफ

ट्रैवल के लिए कहीं निकलना हो और खाने की चीजों को पैक करना कई बार मुश्किल लगता है। खासतौर पर जब मम्मियां हॉस्टल जाते वक्त डिब्बे में अचार भरकर दे देती है। क्योंकि असर उन डिब्बों से तेल लीक हो कर बाहर गिरने लगता है और साथ में रखे दूसरे सामान को गंदा कर देता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो चुका है तो अचार के डिब्बे को लीकप्रूफ बनाने का ये कमाल का हैक जरूर जान लें।

अचार के डिब्बे को लीकप्रूफ बनाने का हैक

एयर टाइट डिब्बे भी कई बार अचार रखने पर धोखा दे देते हैं। उनमे से अचार का तेल, मसाला बह जाता है। और, सारे बैग के साथ सामान में तेल के धब्बे और महक भर जाती है। इस समस्या से बचने के लिए बस इस छोटी सी ट्रिक को ट्राई कर के देख लें। ये ट्रिक प्लास्टिक के डिब्बे को लीकप्रूफ बनाने में मदद करेगी। बस किसी भी प्लास्टिक का डिब्बा जिसमे अचार रखा हो लें। अब एक प्लास्टिक के डिब्बे के आकार से थोड़ा बड़े साइज में काटकर एल्यूमिनियम फॉइल लें। अब ढक्कन को हटाकर डिब्बे के मुंह पर एल्यूमिनियम फॉइल को काटकर डिब्बे के आकार का बना लें। इस एल्यूमिनियम फॉइल को डिब्बे के मुंह पर रखें। ये तरीका भी आपके अचार के तेल को बहने से रोकने में मदद करेगा।

लगातार सिरदर्द हो सकता है जानलेवा

परीक्षा का तनाव और बढ़ा हुआ स्क्रीन टाइम समझकर नजरअंदाज की जा रही लगातार सिरदर्द की शिकायत दरअसल जानलेवा मस्तिष्क रक्तस्राव निकली। मुंबई की 16 वर्षीय एचएससी छात्रा की समय पर की गई आपातकालीन मस्तिष्क सर्जरी से डॉक्टरों ने उसकी जान बचा ली।प्राप्त जानकारी के अनुसार, छात्रा को कई महीनों से तेज सिरदर्द हो रहा था। परिवार ने शुरुआत में इसे पढ़ाई का दबाव, नया चश्मा और मोबाइल-कंप्यूटर के अधिक उपयोग से जुड़ी सामान्य समस्या समझा। लेकिन दर्द बढ़ने पर उसे मुंबई सेंट्रल स्थित वॉकहार्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया।

कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. ऋतुजा उगलमुगले ने जांच के दौरान गंभीर चेतावनी संकेत पहचाने। तत्काल किए गए सीटी स्कैन में दिमाग के भीतर बड़े पैमाने पर रक्तस्राव (इंट्राक्रैनियल ब्लीड) और "मिडलाइन शिफ्ट" पाया गया। डॉक्टरों के अनुसार, ऐसी स्थिति में मरीज के कोमा में जाने या मृत्यु का खतरा अत्यधिक होता है।

जांच में छात्रा के खून में INR स्तर खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ पाया गया। वह बचपन में हुई हृदय सर्जरी के बाद से रक्त पतला करने वाली दवाएं ले रही थी। डॉक्टरों का मानना है कि इन्हीं दवाओं से जुड़ी जटिलता के कारण यह गंभीर रक्तस्राव हुआ।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कंसल्टेंट ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन डॉ. माझदा तुरेल ने तुरंत क्रैनियोटॉमी सर्जरी की। इस प्रक्रिया में दिमाग में जमा खून का थक्का निकालकर दबाव कम किया गया। "अगर समय पर सर्जरी नहीं होती तो स्थायी मस्तिष्क क्षति की आशंका थी," डॉ. तुरेल ने बताया।

सर्जरी के बाद छात्रा करीब तीन सप्ताह तक आईसीयू में भर्ती रही। इसके बाद उसे नियोजित फिजियोथेरेपी दी गई। इलाज का अच्छा असर हुआ और उसकी न्यूरोलॉजिकल स्थिति में लगातार सुधार देखा गया। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, अब वह खतरे से बाहर है।

डॉक्टरों ने इस मामले के जरिए महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि लंबे समय से दवाएं ले रहे बच्चों, खासकर रक्त पतला करने वाली दवाएं लेने वाले मरीजों, को नियमित जांच और फॉलो-अप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। लगातार सिरदर्द, उल्टी, चक्कर आना या व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि देरी जानलेवा साबित हो सकती है।

सिर एवं गर्दन, जठरांत्र, स्तन और रक्त संबंधी कैंसर की अधिकता

विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर मणिपाल हॉस्पिटल्स कोलकाता ने अपनी ऑन्कोलॉजी सेवाओं को और सशक्त करते हुए मणिपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर का शुभारंभ किया। इसके तहत अत्याधुनिक क्लिनिकल हेमेटोलॉजी, हेमेटो-ऑन्कोलॉजी एवं बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) यूनिट की शुरुआत की गई। रोकथाम और प्रारंभिक जांच के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करते हुए अस्पताल ने 'कवच' - सामुदायिक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कार्यक्रम भी लॉन्च किया। यह पहल मणिपाल फाउंडेशन द्वारा कोलकाता नगर निगम (KMC) के सहयोग से शुरू की गई है।

मणिपाल हॉस्पिटल, ईएम बाइपास में आयोजित इस कार्यक्रम में फिरहाद हकीम, माननीय मेयर, कोलकाता नगर निगम; नारायण स्वरूप निगम, आईएएस, प्रधान सचिव (स्वास्थ्य); अनन्या बनर्जी, पार्षद, कोलकाता नगर निगम (वार्ड 109); हरिनारायण शर्मा, सीईओ, मणिपाल फाउंडेशन; डॉ. सुरेंद्र कुमार दाबस, चेयरमैन, मणिपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर एवं ऑन्को रोबोटिक सर्जरीज़, नॉर्थ वेस्ट क्लस्टर; डॉ. मुरली श्रीनिवासन, चीफ ऑफ मेडिकल सर्विसेज, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइज प्रा. लि.; डॉ. अयनाभ देबगुप्ता, रीजनल डायरेक्टर – ईस्ट रीजन; डॉ. सौरव दत्ता, डायरेक्टर – मणिपाल कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर (मुकुंदपुर, साल्ट लेक एवं सिलीगुड़ी क्लस्टर्स); तथा कोमल डाशोरा, क्लस्टर डायरेक्टर – मुकुंदपुर क्लस्टर की गरिमामयी उपस्थिति रही।

कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर केयर सेंटर की शुरुआत पूर्वी भारत के ऑन्कोलॉजी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण कमी को दूर करती है, जहां कैंसर के बढ़ते मामलों के साथ अक्सर देर से निदान और एकीकृत कैंसर सेवाओं की सीमित उपलब्धता देखने को मिलती है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और क्षेत्रीय कैंसर रजिस्ट्रियों के अनुसार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और पूर्वोत्तर राज्यों सहित पूर्वी भारत, देश के कुल कैंसर बोझ का एक बड़ा हिस्सा वहन करता है। इस क्षेत्र में सिर एवं गर्दन, जठरांत्र, स्तन और रक्त संबंधी कैंसर की अधिकता देखी जाती है। लगभग 60% मामलों का निदान उन्नत अवस्था में होता है, जिससे उपचार जटिल हो जाता है और परिणाम अपेक्षाकृत कम अनुकूल रहते हैं। यह केंद्र रोकथाम, स्क्रीनिंग, प्रारंभिक निदान, मेडिकल व सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, सपोर्टिव केयर और सर्वाइवर्शिप सेवाओं को एक समन्वित, मल्टीडिसिप्लिनरी मॉडल के तहत एक ही छत के नीचे प्रदान करने के लिए तैयार किया गया है। आईसीएमआर के अनुमानों के अनुसार, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल मायलोमा जैसे हेमेटो-ऑन्कोलॉजिकल रोग भारत के कुल कैंसर मामलों का लगभग 7–8% हिस्सा हैं, और हर वर्ष 1 लाख से अधिक नए रक्त कैंसर के मामले सामने आते हैं। इन रोगों के लिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक संभावित जीवनरक्षक और उपचारात्मक विकल्प है, लेकिन बड़े महानगरों के बाहर इसकी उपलब्धता सीमित है।

मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान के तहत कोर समिति की बैठक

बेमेतरा। मुख्यमंत्री शिक्षा गुणवत्ता अभियान अंतर्गत जिले की कलेक्टर के निर्देशानुसार गठित कोर ग्रुप के सदस्य के रूप मे प्राचार्य सुनील कुमार झा के द्वारा दिनाँक 28 से 04 फरवरी तक संकुल केंद्र नरी,छीतापार, खाम्ही,झाल एवं बिलाई के प्राचार्य , प्रधान पाठकों एवं संकुल समन्वयकों की बैठकें लेकर विभिन्न दिशा-निर्देश दिये गये। उन्होंने आगामी 5 वी, 8 वी, 10 वी कक्षा के विद्यार्थियों के गुणवत्ता पूर्ण परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित बिंदुओं पर कार्य योजना बना कर शीघ्र क्रियान्वयन हेतु मार्गदर्शन प्रदान किया। कमजोर विद्यार्थियों को चिन्हांकित कर विशेष अतिरिक्त कक्षाओं के माध्यम से उन्हें परीक्षा के लिए तैयार करने, अनुपस्थित बच्चों को कक्षा मे उपस्थित कराने प्रयास, प्रतिभावान विद्यार्थियों को विशेष मार्गदर्शन देने, पूर्व वर्षो के प्रश्न पत्रों को हल करवाना,उत्तर लेखन का अभ्यास, शिक्षकों के कार्यो की समीक्षा एवं मार्गदर्शन जैसे बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा कर दिशानिर्देश दिया गया। उक्त बैठकों में संकुल केंद्रों के समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रमुख एवं संकुल समन्वयक उपस्थित रहे।

नगर पंचायत के सेवानिवृत्त कर्मचारी को विदाई निकाय के दिवंगत कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि

डोंगरगांव नगर। नगर पंचायत के कार्यरत कर्मचारी वाहन चालक हरि श्रीवास सेवानिवृत्त हो गए हैं। सेवानिवृत्त होने पर नगर पंचायत द्वारा विदाई समारोह आयोजित कर अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की मौजूदगी में ट्रेक्टर चालक हरि श्रीवास को भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर जीवनोपयोगी उपहार एवं स्मृति चिन्ह् भेटकर सम्मानित किया गया। नगर पंचायत सभाकक्ष में आयोजित संक्षिप्त विदाई समारोह में सर्वप्रथम नगर पंचायत अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी, नगर पंचायत उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता, मुख्य नगर पालिका अधिकारी विनम्र जेमा की मौजूदगी में निकाय के पूर्व में दिवंगत कर्मियों मनोज यादव एवं मंथीर मालेकर को श्रद्धांजलि दी गई। उपरांत समस्त जनप्रतिनिधियों एवं कर्मचारियों ने श्रीवास को उपहार भेंट कर सुखद जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर पार्षद गीता सलामे, पदमनी ठाकुर, कोमल साहू, सद्दाम खत्री, लेखापाल विवेक भारद्वाज, अभियंता केआर बर्मन, उमा पाल, गिरीश साहू, ताराचंद रामटेके, महेश बैस, टामन पटेल, खेलेंद्र नायक, संतोष ठाकुर, छन्नू साहू, दानेश्वर साहू व शिव पांडे सहित समस्त स्टॉफ मौजूद थे।

मंत्री से स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार की मांग नपंअध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा मांग पत्र

डोंगरगांव नगर। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल को नगर पंचायत डोंगरगांव की अध्यक्ष श्रीमती अंजू त्रिपाठी ने मांग पत्र सौंपा है। श्रीमती त्रिपाठी ने मांग पत्र के माध्यम से नगर पंचायत क्षेत्र में आवश्यक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उक्त मांग पत्र पर स्वास्थ्यमंत्री ने सकारात्मक कदम उठाने की बात कही है। नगर पंचायत अध्यक्ष अंजू त्रिपाठी ने मांग पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि नगर पंचायत क्षेत्र में नागरिकों को स्वास्थ्य संबंधी मूलभूत सुविधाओं के अभाव का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या एवं जरूरतों को ध्यान में रखते हुए शासकीय चिकित्सालय में सुविधाओं का विस्तार अत्यंत आवश्यक हो गया है। पुराने चिकित्सालय परिसर में ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) की व्यवस्था प्रारंभ करने, शासकीय चिकित्सालय में स्वर्ग रथ एवं मुक्तांजलि वाहन (शव वाहन) की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा शासकीय चिकित्सालय में दो नग कॉफिन फ्रीजर उपलब्ध कराने की मांग की गई है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि अस्पताल में आवश्यक सुविधाओं के अभाव में आम नागरिकों को इलाज एवं अन्य आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे समय, धन एवं संसाधनों की अनावश्यक हानि होती है। नपंअध्यक्ष ने स्वास्थ्य मंत्री से मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया है।

सहयोग संस्था द्वारा विरोध के बाद भी राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को काट दिया गया

बेमेतरा। मोहभट्टा गार्डन के सामने राष्ट्रीय वृक्ष बरगद जो मोहभट्टा उद्यान के बाहर शान से खड़ा था जो विगत पचासो वर्ष से राहगिरो को शीतल छाव पक्षीयो का बसेरा और लोगो को चौबीसो घंटे शुद्ध आक्सीजन प्रदान करता था और लोगो की धार्मिक आस्था का केंद्र और वो बरगद किसी को भी कोई हानि नही पहुंचा रहा था आज मौका परस्त लोगो की लालच का भेठ चढ़ गया। प्रसासन और ठेकेदारो की मानमानी और मिली भगत से सैकड़ो वर्ष जीने वाला बरगद का पेड़ बिना अनुमति काटा जा रहा था जिसे सहयोग नें तत्परता दिखाते हुए बचाने का प्रयास किया 04माह संघर्ष के बाद प्रसासनिक मिलीभगत से बिना किसी विशेष और प्रशासनिक उपस्थिति में बरगद को सिफ्टिंग के नाम पर उखाड़ कर गड्डे में डाल दिया गया और आपत्ति कर्ता सहयोग को सुचना भी देना उचित नही समझा गया। एक बरगद आज से कुछ वर्ष पूर्व राजनैतिक स्वार्थ के चलते उखाड़ा गया था तो वो राजनेता ही उखड़ गए उस समय भी सहयोग नें विरोध दर्ज किया था और पुनः वही घटना दोहराई जा रही हैं। वन विहीन बेमेतरा में प्रशासन की मानमानी यह प्रसासन का बहोत ही निंदनीय कार्य हैं जो ठेकेदारो के दबाव में आ कर राष्ट्रीय सम्पदा बरगद को नष्ट कर दिया गया। सहयोग जो बेमेतरा क्षेत्र में लगातार पौधरोपण कर उनका संरक्षण करता है प्रशासन नें उनका पूछना सुनना भी उचित नही समझा और एकतरफा कार्य करते हुए बरगद को उखाड़ दिया गया सहयोग बेमेतरा इसका पुरजोर विरोध करता है।

शिक्षा के साथ संस्कार जरूरी है: विधायक दीपेश साहू

बेमेतरा। बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सलधा मे स्थित शहीद भगत सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर बेमेतरा विधायक दीपेश साहू मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत विधायक दीपेश साहू द्वारा भारत माता, मां सरस्वती एवं छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन कर की गई। इसके पश्चात विद्यालय के नन्हे-नन्हे छात्र-छात्राओं द्वारा मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ दी गई, जिन्हें देखकर उपस्थित अतिथियों एवं दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बच्चों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय के छात्र-छात्राओं की प्रतिभा, आत्मविश्वास और मंचीय प्रस्तुति की सभी ने मुक्त कंठ से सराहना की। इस अवसर पर मेधावी एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मान राशि एवं पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए विधायक दीपेश साहू ने कहा बच्चे देश का भविष्य होते हैं। शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक एवं नैतिक मूल्यों का विकास भी उतना ही आवश्यक है। ऐसे वार्षिक उत्सव बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ग्रामीण अंचल के विद्यालयों में बच्चों की प्रतिभा देखकर यह विश्वास और मजबूत होता है कि आने वाला भविष्य उज्ज्वल है। उन्होंने शिक्षकों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि शिक्षक बच्चों को सही दिशा देने वाले मार्गदर्शक होते हैं। साथ ही उन्होंने ग्रामवासियों से बच्चों की शिक्षा में हरसंभव सहयोग करने की अपील की। कार्यक्रम में सोसायटी अध्यक्ष अध्यक्ष बिसन साहू, विधायक प्रतिनिधि किशुन साहू, संतोषी अश्विन निषाद जनपद सदस्य, मंडल अध्यक्ष सेवाराम साहू, सरपंच सियाराम सिन्हा उपसरपंच चित्रलेखा साहू कुमार साहू डॉक्टर सुभाष तिवारी अध्यक्ष शाला प्रबंधन समिति एवं विकास समिति लुकेश साहू सहित जनप्रतिनिधिगण, ग्राम पंचायत के पंचगण, शिक्षकगण, विद्यालय के छात्र-छात्राएं एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे।

बाल संरक्षण विषय पर जिला से 10 शिक्षक प्रशिक्षित

दल्लीराजहरा। राज्य बाल संरक्षण समिति ने बच्चों की देखरेख व संरक्षण को लेकर प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन 29 जनवरी से 31 जनवरी तक किया गया । बच्चों के देखरेख व संरक्षण से संबंधित नियमों के संबंध में स्कूली बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से मास्टर ट्रेनर्स का प्रशिक्षण निमोरा रायपुर में आयोजित किया गया । इसमें जिले के 10 शिक्षकों ने भाग लिया । कार्यक्रम में दुर्ग संभाग के प्रशिक्षकों के साथ पेरेंटिंग एक्सपर्ट चिरंजीवी जैन ने विशेष चर्चा की । श्री जैन ने बच्चों के मानसिक विकास, सकारात्मक पालन पोषण, भावनात्मक सहयोग और व्यवहार संबंधी समस्याओं पर विस्तार से जानकारी दी । इस अवसर पर डौंडी तुका राम साहू शा. पूर्व मा शा खल्लारी , मोना रावत शा पूर्व मा. शा. मरदेल, डौंडी लोहारा मनीष देशमुख शा. पूर्व मा. शा. बगईटोला, लता साहू शा. प्रा. शा. कोटेरा, बालोद मनीष वैदे शा. पूर्व मा. शा. बघमरा, भगवती सिन्हा शा. प्रा. शा. गंजपारा, गुरूर अजय वर्मा शा. पूर्व मा. शा. पेरपार, पूर्णिमा बघेल शा प्रा. शा. चन्दनबिरही, गुंडरदेही गोकुल राम राउत शा. पूर्व मा. शा. सिर्री, सुमन देवांगन शा. प्रा. शा.कांदुल शामिल रहे ।

विधायक भावना बोहरा के प्रयासों से रेंगाबोड़ कुंडा व्यपवर्तन योजना को 63.80 करोड़ की मंजूरी

कवर्धा। कवर्धा– पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के किसानों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में रेंगाबोड़ (कुंडा) व्यपवर्तन योजना को ?63 करोड़ 80 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। विधायक भावना बोहरा के सतत प्रयासों से स्वीकृत इस बहुप्रतीक्षित योजना से बनियाकुबा, रेंगाबोड़ (कुंडा), ओड़ाडबरी, लोखान, सेन्हाभाटा, दुल्लापुर, बर्घरा एवं भुवालपुर सहित आसपास के ग्रामों के हजारों किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। परियोजना के पूर्ण होने पर लगभग 1620 हेक्टेयर खरीफ क्षेत्र में सुनिश्चित सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे किसान अब केवल मानसून पर निर्भर नहीं रहेंगे और कृषि उत्पादन व आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। विधायक भावना बोहरा ने इस स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह योजना केवल सिंचाई परियोजना नहीं, बल्कि किसान सशक्तिकरण, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती और क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक निर्णायक कदम है। डबल इंजन भाजपा सरकार किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पंडरिया विधानसभा में लगातार विकास कार्यों को गति दे रही है।

चूहा खा गए बोलने पर अफसर निलंबित, लेकिन धान सूखने के असली जिम्मेदारों पर मेहरबानी क्यों?

एफआईआर और वसूली से बच रहा सिस्टम

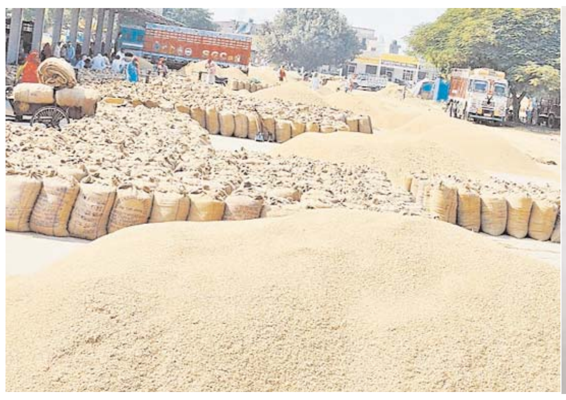

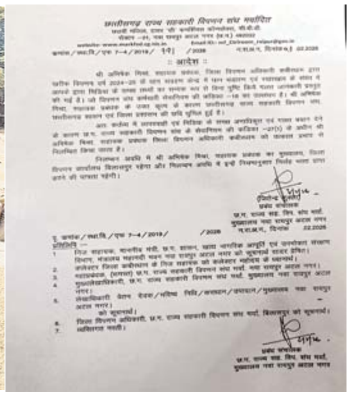

कवर्धा। धान खरीदी और भंडारण में सामने आई गंभीर अनियमितताओं के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई अब सवालों के घेरे में है। मीडिया के सामने धान की कमी को लेकर चूहा खा गया जैसा बयान देने पर सहायक प्रबंधक अभिषेक मिश्रा को तो तत्काल निलंबित कर दिया गया, लेकिन जब धान सूखना प्रमाणित हो चुका है, तब संग्रहण केंद्र बाजार चारभाटा के वास्तविक प्रभारी पर की गई कार्रवाई आधी-अधूरी नजर आ रही है। सूत्रों के अनुसार, धान के सूखने की प्रामाणिक पुष्टि के बाद संग्रहण केंद्र प्रभारी को केवल निलंबित कर विभागीय जांच संधारित कर दी गई, जबकि यह मामला सीधे तौर पर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आता है। नियमों के मुताबिक ऐसे मामलों में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराना और नुकसान की वसूली की कार्रवाई अनिवार्य मानी जाती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बयान देने वाले अधिकारी पर तो त्वरित और कठोर कार्रवाई हो गई, लेकिन धान के सूखने जैसी गंभीर लापरवाही, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ, उस पर एफआईआर क्यों नहीं? क्या विभागीय जांच के नाम पर जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? जानकारों का कहना है कि धान का सूखना केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि भंडारण और रखरखाव में घोर लापरवाही का प्रमाण है। ऐसे मामलों में केवल निलंबन पर्याप्त नहीं, बल्कि आर्थिक क्षति की भरपाई और आपराधिक जिम्मेदारी तय होना जरूरी है।इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं– क्या कार्रवाई बयान पर होती है, नुकसान पर नहीं? और क्या असली दोषियों तक कानून का शिकंजा कभी पहुंचेगा, या फिर फाइलों में जांच दबकर रह जाएगी?

श्रीमद् भागवत कथा पुराण में माखन चोर की लीला का वर्णन किया गया

बेमेतरा। जिला मुख्यालय बेमेतरा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बाबा महोतरा चल रहे श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान गंगा कथा व्यास संत श्री गणेश्वर शास्त्री जी महाराज के श्री मुख से प्रवाहित हो रही है जिसमें आसपास की जनमानस भगवान की दिव्य चरित्र को सुनने के लिए पहुंच रहे हैं पूर्व सरपंच मोहन साहू के द्वारा आयोजित भागवत कथा को सुनने के लिए आसपास के ग्रामीण सहित पारिवारिक जन पहुंच रहे हैं कथा शास्त्री जी महाराज के द्वारा भगवान की दिव्य चरित्र का श्रवण कराया जा रहा है भगवान ने किस प्रकार सृष्टि का विस्तार किया किस प्रकार भगवान भक्तों की रक्षा के लिए विविध अवतार लेकर गौ माता ब्राह्मण संत वेद भक्त पृथ्वी की रक्षा के लिए बैकुंठ की सुख को त्याग कर भगवान नंगे पग चलते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिव्य जन्मोत्सव मनाया गया भगवान ने किस प्रकार बाल लीला करके सभी ब्रज वासियों को आनंदित किया भक्तों को आनंदित किया मां को आनंदित किया माखन चोरी के माध्यम से भगवान ने अनेक भक्तों के पापों का हरण कर लिया पश्चात कथा में माखन चोरी के दिव्य झांकी को प्रस्तुत किया गया।

मुख्यमंत्री साय ने किया 'वूमेन फॉर वेटलैण्ड्स' अभियान पोस्टर का अनावरण

बेमेतरा। विश्व आर्द्रभूमि दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने मुख्यमंत्री निवास में 'वुमेन फॉर वेटलैण्ड्स ' अभियान के पोस्टर का अनावरण किया,इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश में आर्द्रभूमि एवं प्राकृतिक जल-स्रोतों के संरक्षण हेतु चलाए जा रहे इस अभियान की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जल ही जीवन है और आर्द्रभूमियां मानव सभ्यता की अमूल्य धरोहर हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति को इस पवित्र अभियान से जोड़ना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रेरणादायी कदम है। मुख्यमंत्री साय ने यह भी कहा नदियां, तालाब, कुएं, पोखर और आर्द्रभूमियां केवल जल-स्रोत नहीं, बल्कि जीवनदायिनी प्रकृति की पहचान हैं। इन्हें बचाना हम सभी का सामूहिक दायित्व है। 'वूमेन फॉर वैटलैंड्स ' अभियान की संस्थापक एवं भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रज्ञा निर्वाणी द्वारा प्रदेशभर में आर्द्रभूमि संरक्षण हेतु निरंतर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है,इस अभियान के अंतर्गत तालाब, नहर, कुएं, नदियों एवं प्राकृतिक जल-स्रोतों के संरक्षण के लिए महिलाओं को संगठित किया जा रहा है। प्रज्ञा निर्वाणी ने मुख्यमंत्री को नवागढ़ स्थित गिधवा-परसदा-नगधा पक्षी विहार क्षेत्र को रामसर साइट घोषित करने हेतु ज्ञापन भी सौंपा, सी एम साय ने कहा महिलाएं प्रकृति की प्रथम संरक्षक हैं,यदि मातृशक्ति आगे आएगी तो जल-स्रोतों का संरक्षण जन-आंदोलन बन जाएगा पोस्टर अनावरण कार्यक्रम के दौरान प्रसन्ना अवस्थी, प्राची शर्मा, प्रणीता शर्मा,आरविका अवस्थी सहित अन्य गणमान्यजन उपस्थित रहे।

विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जिले में चलाए जा रहे हैं स्वच्छता अभियान

दल्लीराजहरा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील चंद्रवंशी के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण अंतर्गत जिले के स्कूलों में स्वच्छता के प्रचार-प्रसार हेतु विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

इस दौरान स्कूलों के छात्र-छात्राओं को स्वच्छता की जानकारी दी जा रही है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को व्यक्तिगत स्वच्छता, विद्यालय एवं घर की साफ-सफाई, शौचालय के सही उपयोग कचरे के पृथक्करण, खुले में शौच न करने जैसे विषयों पर जानकारी दी जा रही है। सभी विद्यार्थियों को स्वच्छता बनाए रखने, गंदगी न फैलाने एवं दूसरों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित करने की शपथ भी दिलाई जा रही है। इस दौरान स्कूली बच्चें भी उत्साहपूर्वक शपथ लेते हुए अपने विद्यालय और गांव को स्वच्छ रखने का संकल्प ले रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अब तक जिले के 36 स्कूलों के लगभग 3500 छात्र-छात्राओं को स्वच्छता हेतु प्रति प्रेरित किया गया है। समन्वयकों द्वारा बताया गया कि बचपन से स्वच्छता की आदतें विकसित करने से ही स्वच्छ समाज का निर्माण संभव है बच्चे समाज की नींव है वे अपने परिवार एवं समाज को भी प्रेरित करते हैं।

किसानों के धान खरीदी की तिथि बढ़ाने पर शर्मा ने किया आभार यक्त

बेमेतरा। कल मुख्यमंत्री निवास रायपुर में भारतीय जनता पार्टी के रायपुर शहर जिला प्रभारी एवं पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा बेमेतरा राजेन्द्र शर्मा ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी से सौजन्य भेंट कर महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की।

इस अवसर पर शर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा धान खरीदी की तारीख बढ़ाए जाने संबंधी निर्णय का हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला प्रदेश के लाखों किसानों के लिए राहत देने वाला और पूरी तरह जनहितकारी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी लगातार किसान, गरीब और गाँव के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए संवेदनशील निर्णय ले रहे हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेशवासियों को मिल रहा है। राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि दो दिन 5 एवं 6 फरवरी को धान खरीदी होगी जिन किसान का आवेदन समिति को मिला होगा या जिनका टोकन कटा होगा या जिसका सत्यापन हो गया होगा वो सभी किसान धान बेचने के लिए पात्र होंगे। राजेन्द्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश में जारी धान खरीदी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और सुचारु बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं लगातार निगरानी कर रहे हैं। किसानों की चिंता करते हुए तारीख बढ़ाने का निर्णय प्रदेश सरकार की किसान-समर्पित कार्यशैली का स्पष्ट प्रमाण है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ राज्य विकास, सुशासन और पारदर्शिता की नई ऊँचाइयों को प्राप्त करेगा । राजेन्द्र शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुवे कहा कि उन्होंने किसानों को भड़काने का असफल प्रयास किया है किसानों को पूरी उम्मीद थी कि धान खरीदी की तारीख बढ़ेगी वो कांग्रेसियों के भड़कावे में नहीं आए । राजेन्द्र शर्मा नेकहा की जबकांग्रेस की प्रदेश में सरकार थी तो उन्होंने किसानों को दो साल का बोनस नहीं दिया और अंतर की राशि को चार किस्त में दिया जबकि भाजपा की विष्णु देव की सरकार ने तुरन्त दो साल का बोनस दिया और धान खरीदी के बाद अंतर की राशि एकमुश्त दी है और इस साल फिर देगी ।

5 एवं 6 फरवरी को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जाएगी

दल्लीराजहरा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णय अनुसार 05 एवं 06 फरवरी को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर्गत किसानों के धान की खरीदी की जाएगी। इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अवर सचिव भूपेन्द्र सिंह राजपूत ने दिशा-निर्देश जारी कर संबंधित धान खरीदी केन्द्रों में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दिशा-निर्देश जारी कर किसानों के हित में समर्थन मूल्य में धान खरीदी की समय अवधि में 02 अतिरिक्त दिवस 05 एवं 06 फरवरी तक वृद्धि किया है। जारी निर्देशों के अनुरूप ऐसे किसान जिनके द्वारा 10 जनवरी 2026 पश्चात् टोकन हेतु आवेदन किया गया है, परंतु सत्यापन नहीं हो पाया है। ऐसे किसान जिनके द्वारा 10 जनवरी 2026 पश्चात आवेदन किया गया है एवं सत्यापन उपरांत धान पाया गया है तथा ऐसे किसान जिन्होंने 28, 29 एवं 30 जनवरी को टोकन प्राप्त किया है परंतु किसी कारणवश धान विक्रय नहीं कर पाए हैं। उक्त किसानों का धान आगामी 05 एवं 06 फरवरी को संबंधित धान उपार्जन केन्द्रों में खरीदा जाएगा। कलेक्टर दिव्या मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि आगामी 05 एवं 06 फरवरी को जिले के धान खरीदी केन्द्रों में जहाँ ऐसे किसान हों उनका सुव्यवस्थित रूप से धान की खरीदी करना सुनिश्चित करें।

ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में योजना को क्रांतिकारी पहल बताया

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने वीबी-जी राम जी योजना का सफल क्रियान्वयन करने कहा

दुर्ग/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण की बैठक के दौरान वीबी-जी राम जी योजना को ग्रामीण आजीविका के क्षेत्र में क्रांतिकारी योजना बताया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई यह योजना एक नई ग्रामीण रोजगार योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देना है। यह योजना मनरेगा की जगह पर शुरू की गई है और इसमें कई नए प्रावधान किए गए हैं।

वीबी-जी राम जी योजना के मुख्य बिंदु- रोजगार की गारंटी- इस योजना के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में 125 दिनों का रोजगार दिया जाएगा। जो पूर्व में केवल 100 दिवस रोजगार प्रदाय करता था। इसके साथ ही अगर काम नहीं मिलता है, तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। मजदूरी का भुगतान एक सप्ताह के भीतर किया जाएगा। अगर मजदूरी का भुगतान 15 दिनों के भीतर नहीं किया जाता है, तो 0.05 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाएगा। योजनांतर्गत ग्राम पंचायत को योजना बनाने और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है।

वीबी-जी राम जी योजना का बजट प्रावधान - 2026-27 के लिए बजट 95,692.31 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्ववर्ती बजट 88,000 करोड़ रुपये (मनरेगा के लिए) निर्धारित था। मुख्यमंत्री ने योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन करते हुए ग्रामीण

अर्थव्यवस्था को मजबूत करने कहा।

आईटी हब के क्षेत्र में दुर्ग भिलाई में बढ़ा ऐतिहासिक कदम, आईटी के 40 कंपनियों एवं निवेशकों के बीच एमओयू हुआ-मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अगुवाई में अब दुर्ग भिलाई आईटी के क्षेत्र में नए क्रांतिकारक ऐतिहासिक कदम में दस्तक देने जा रहा है। आज मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में 40 आईटी कंपनियों और आईटी के निदेशकों के बीच एमओयू पर अनुबंध हुआ। इससे आईटी शिक्षा के क्षेत्र ऐतिहासिक कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने यस चिट फंड कंपनी के निवेशकों को सौंपी डूबे हुए निवेश की राशि, चिटफंड कंपनी के निवेशकों का भविष्य सदृढ़, भविष्य का बुनियादी सपने गढ़ सकेंगे छत्तीसगढ़ शासन सुशासन के साथ ही सुचिता के साथ प्रदेश के नागरिकों का भविष्य को सुरक्षित और सुदृढ़ करने की दिशा में सार्थकता, संकल्प के साथ कार्य कर रही है। इस दिशा में आज दुर्ग में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की उपस्थिति में यस चिट फंड कंपनी के निवेशकों को उनके द्वारा निवेश किए गए राशि का चेक भेट किया गया। इसके अंतर्गत 4601 हितग्राहियों को 7 करोड़ 38 लाख 24100 की राशि का चेक प्रदाय किया गया। प्रतीक स्वरूप मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हितग्राहियों को लाभांवित किया। यह दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन आमजनों के हित के साथ कदम मिलाकर खड़ी है। उन्होंने कहा कि आमजनों के साथ धोखाधड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को बक्सा नहीं जाएगा। भ्रष्ट व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किया जाएगा।

बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था, 15 दिनों का अल्टीमेटम, कांग्रेसी बोले होगा एसपी आफिस का घेराव

भारी वाहनों के बेतरतीब प्रवेश से हो रही परेशानी

यातायात नियमों का पालन नहीं, बन रही जाम की स्थिति

राजनांदगांव7 शहर में लगातार बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया हे। कांग्रेसयों ने एसपी अंकिता शर्मा को ज्ञापन सौंपकर व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। वहीं 15 दिनों का अलअीमेटम में दिया है, इसके बाद सीधे एसपी कार्यालय का घेराव करने की बात कही है। शहर में बेरोकटोक भारी वाहनों की आवाजाही, बसों के मनमाने स्टापेज, चौक-चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस की अनुपस्थिति और बेतरतीब पार्किंग के चलते आम नागरिकों को भारी दबाव और जाम की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। चार पहिया और तीन पहिया वाहनों की आवाजाही सबसे अधिक प्रभावित हो रही है, जिससे दैनिक जीवन और व्यापारिक गतिविधियां बाधित हो रही हैं। इसके साथ ही नेशनल हाइवे में बंद पड़ी हाईमास्ट लाइटों के कारण रात के समय दुर्घटना की आशंका भी बढ़ गई है। इस अवसर पर जिला शहर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र मुदलियार ने कहा कि नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार की व्यापक गुंजाइश है, लेकिन इसके लिए जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम प्रशासन को संयुक्त रूप से कार्ययोजना बनाकर अमल करना होगा। केवल एक विभाग के प्रयास से स्थिति नहीं सुधर सकती। मुदलियार ने स्पष्ट कहा कि यातायात सुधार के नाम पर आम नागरिकों और व्यापारियों को परेशान करना स्वीकार्य नहीं है। व्यवस्था इस तरह बनाई जाए कि सर्विस लेन और प्रमुख चौक-चौराहों पर आवागमन सुगम हो, भारी वाहनों के दबाव को नियंत्रित किया जाए और बसों को तय स्टापेज पर ही रोका जाए। जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि इन समस्याओं पर तत्काल संज्ञान लेते हुए ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि राजनांदगांव की जनता को जाम, अव्यवस्थित ट्रैफिक और अनावश्यक परेशानी से राहत मिल सके। मुदलियार ने कहा कि जनता से जुड़ी इन समस्याओं पर अगर 15 दिनों में सुधार लागू नहीं हुए तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव किया जाएगा।

संभाग स्तरीय रोजगार मेला 16 एवं 17 फरवरी को सरगुजा में

जशपुरनगर। प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरगुजा में 16 एवं 17 फरवरी 2026 को संभाग स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मेला में सहभागिता हेतु ऑनलाइन पोर्टल erojgar.cg.gov.in या छत्तीसगढ़ रोजगार एप में ऑनलाईन पंजीयन कर सकते है। ऐसे आवेदक जिन्होनें ऑनलाईन पोर्टल erojgar.cg.gov.in या छत्तीसगढ़ रोजगार एप में रोजगार पंजीयन एवं रोजगार मेला हेतु पंजीयन नहीं करवाया है, वे पोर्टल पर अपना पंजीयन करवा सकतें है। एवं अपने समस्त शैक्षणिक योग्यता, पासपोर्ट साईज फोटो, पहचान पत्र, अनुभव प्रमाण पर इत्यादि दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि को उपस्थित हो सकतें है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय जशपुर से सम्पर्क किया जा सकता है।

स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्कल ने मेधावी छात्र का किया सम्मान

हिमांशी गुप्ता ने नेट परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर क्षेत्र को किया गौरवान्वित

रामानुजगंज। नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 15 निवासी सुनील गुप्ता की सुपुत्री हिमांशी गुप्ता ने यूजीसी नेट परीक्षा में 97% अंक प्राप्त कर अपने परिवार सहित पूरे नगर पालिका क्षेत्र का नाम रोशन की है। गौरतलम हिमांशी गुप्ता नगर पंचायत रामानुजगंज के पूर्व पार्षद स्वर्गीय रामचंद्र गुप्ता की पोती हैं। इस बात की खबर जैसे ही स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल के सदस्यों को लगी तो शैलेष कुमार गुप्ता अधिवक्ता जयप्रकाश गुप्ता वार्ड के पार्षद सिद्धांत यादव अश्वनी गुप्ता शुभम गुप्ता ने उनके घर पहुंच कर हिमांशी गुप्ता सहित उनकी माता ज्योति गुप्ता और पिता सुनील गुप्ता से मुलाकात कर पूरे परिवार की उपस्थिति में हिमांशी गुप्ता को साल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शैलेष कुमार गुप्ता ने कहां की हिमांशी गुप्ता का मेहनत और लगन इस बात को प्रमाणित करता है कि अपने उज्जवल भविष्य कि इन्हें पूरा ख्याल है उसी का परिणाम है कि रामानुजगंज का नाम रोशन की है इन्हें मैं जीवन में और तरक्की करने का ईश्वर से कामना करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि विवेकानंद स्टडी सर्किल ऐसे विद्यार्थियों का हमेशा से सहयोगी के रूप में उपस्थित रहा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस उपलब्धि की सूचना जब रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय रामविचार नेताम को दी गई तो उन्होंने दूरभाष के माध्यम से हिमांशी गुप्ता का हौसला अफ्जाई करते हुए उन्हें जीवन में आगे बढ़ाने और सहयोग करने की बात करते हुए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी।

रामविचार नेताम कहा कि उन्नति करने वाले छात्राओं को यदि हौसला अफ्जाई किया जाए तो उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की कई प्रेरणा स्रोत मिलती है। उन्होंने यह भी कहा कि जब मैं रामानुजगंज आऊंगा तो सार्वजनिक मंच से उनका पुनः सम्मान करते हुए हौसला अफ्जाई किया जाएगा। हिमांशी गुप्ता के माता-पिता सहित सभी परिवार के सदस्यों ने अपनी पुत्री का सम्मान करने वाले एवं सहयोग करने की बात करने वालों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उनका आभार माना।

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड स्थित प्राथमिक शाला में भव्य वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन

भाटापारा। नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री वार्ड स्थित प्राथमिक शाला में भव्य वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन उत्साहपूर्वक संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, अभिभावकों, शिक्षकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर विद्यालय के नन्हे विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों-गीत, नृत्य, नाट्य एवं रचनात्मक प्रस्तुतियों-ने उपस्थितजनों का मन मोह लिया। बच्चों की प्रतिभा, अनुशासन, मंचीय आत्मविश्वास और प्रस्तुति की परिपक्वता देखकर सभी अभिभूत हुए। कार्यक्रम के माध्यम से विद्यार्थियों की बहुआयामी क्षमताएँ उजागर हुईं, जो विद्यालय में दिए जा रहे गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन का प्रत्यक्ष प्रमाण है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर पालिका अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने कहा कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। ऐसे आयोजनों से बच्चों में आत्मविश्वास, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता और सांस्कृतिक मूल्यों का विकास होता है। उन्होंने शिक्षकों के समर्पण, सतत परिश्रम तथा अभिभावकों के सहयोग की सराहना करते हुए कहा कि यही समन्वय विद्यालय को नई ऊँचाइयों तक ले जाता है। विद्यालय परिवार द्वारा आयोजित यह वार्षिकोत्सव कार्यक्रम सुव्यवस्थित, प्रेरणादायक एवं सफल रहा। अंत में प्रतिभागी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इस अवसर पर सभापति कुंजराम कोशले, पार्षद बंटी टंडन पार्षद प्रतिनिधि संजय बंजारे कीर्तन जायसवाल माखन महिलांगे पुरषोत्तम महिलांगे विकासखंड शिक्षा अधिकारी भास्कर देवांगन बी आर सी दुर्गेश शर्मा समन्वयक मुकेश देवांगन एवं समस्त शिक्षक शिक्षिकायें एवं पालकगण वार्डवासी मौजूद रहे।

रायपुर से राजनांदगांव तस्करी, 15 किलो गांजा के साथ तीन आरोपी अरेस्ट

टेडेसरा के पास पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान की कार्रवाई

राजनांदगांव। सोमनी पुलिस ने तीन गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने पास से पुलिस ने 14 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया है। आरोपी गांजा की खेप को रायपुर से राजनांदगांव ला रहे थे, जिसकी सूचना के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जब्त गांजा की कीमत तकरीबन 73 हजार रुपए आंकी गई है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रायपुर से राजनांदगांव की ओर आ रहे आटो वाहन (सी. जी. 04 क्यू.एफ 3543) को ग्राम टेडेसरा में एमसीपी लगाकर रोका गया। चेक करने पर आटो में 08 छोटे-बड़े पैकेटों में 14.662 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। आरोपियों ने बताया कि वे राजनांदगांव बिक्री करने के लिए गांजा को ला रहे थे। पुलिस अधिकारियों ने मौके से आरोपी दुर्गेश रायकर उर्फ विक्की पिता राजकुमार रायकर ग्राम हीरापुर लाटरी नगर रायपुर, मो0 जुल्फिकार उर्फ राजा पिता मोह0 सफी खान निवासी कबीर नगर अटल आवास रायपुर और दीपक साहू पिता सुकदेव निवासी कबीर नगर अटल आवास रायपुर को अरेस्ट किया गया। आरोपियों के कब्जे से एक महेन्द्रा कम्पनी का इलेक्ट्रीक ऑटो कीमती दो लाख रूपए बताई गई है।

समस्याओं के त्वरित, संवेदनशील एवं प्राथमिकता से निराकरण के दिए निर्देश

जशपुरनगर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने गृह ग्राम बगिया में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित कर क्षेत्रवासियों से प्रत्यक्ष संवाद किया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीणों एवं आम नागरिकों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपनी समस्याएं, मांगें एवं सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखे। मुख्यमंत्री साय ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे प्रत्येक व्यक्ति की बात गंभीरता से सुनी और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार आम जनता की समस्याओं के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा जनदर्शन जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से सीधे जनता से संवाद कर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के साथ हल किया जा रहा है।कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों ने सड़क, पेयजल, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया।

सरकार ओबीसी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सक्रिय है और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रही है - मुख्यमंत्री साय

मुख्यमंत्री ने अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए निर्धारित कार्य योजना पर की विस्तृत समीक्षा, मुख्यमंत्री ने स्वीकृत विकास कार्यों को आगामी दो माह की समय सीमा में पूर्ण करने दिए निर्देश

दुर्ग,/ मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की प्रथम बैठक जिला मुख्यालय दुर्ग के लोक निर्माण विभाग के सभाकक्ष में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत स्वीकृत प्रमुख कार्यों, प्राधिकरण मद से निर्माणाधीन विकास कार्यों का अनुमोदन एवं प्रावधानित बजट सहित नवीन स्वीकृत कार्यों पर विस्तृत समीक्षा के साथ-साथ माननीय जनप्रतिनिधियों की सुझाव पर चर्चा हुई। प्राधिकरण की प्रथम बैठक में अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए चलाए जा रहे योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की स्थिति के क्षेत्र में यह महत्वपूर्ण बैठक थी। बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के पिछड़ा वर्ग समुदाय के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान के लिए चलाये जा रहे योजनाओं की प्रगति का आकलन करना और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा करना था।

मुख्यमंत्री ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के अंतर्गत संचालित विभिन्न निर्माण कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि बजट का सही समय पर और पूर्ण उपयोग सुनिश्चित किया जाए ताकि विकास का लाभ सीधे हितग्राहियों तक पहुँचे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिले के अंतर्गत स्वीकृत सभी विकास कार्यों, सेवाओं और कार्यक्रमों का बेहतर संचालन करते हुए सीधे तौर पर अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के हित को ध्यान में रखकर सभी स्वीकृत निर्माण कार्यों को अविलंब पूर्ण करें। मुख्यमंत्री ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 से लेकर वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों, विकास कार्यों की जिलेवार समीक्षा की। समीक्षा बैठक में ऐसे विकास कार्य जो अप्रारंभ एवं प्रगतिरत है, ऐसे विकास कार्यों को दो महीने की समय सीमा में पूर्ण करने निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का उद्देश्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्यक्रम का बेहत्तर संचालन करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किया जाना है। मुख्यमंत्री ने जिला कलेक्टरों से चर्चा कर विकास कार्यों की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उल्लेखनीय है कि

छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण विकास की प्रक्रिया में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना है। राज्य के ग्रामीण एवं नगर पंचायत के विकास के लिए क्षेत्रीय नेतृत्व से सलाह प्राप्त कर अल्पकालिक योजनाओं का निर्माण किया जाना है। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ढांचागत विकास कार्यों, बुनियादी सुविधाओं के स्तर तक क्रमबद्ध तरीके से पहुंच सुनिश्चित किया जाना है। जन अपेक्षा के अनुरूप छोटे-छोटे निर्माण कार्यों की त्वरित स्वीकृति दिया जाना है। विकास से संबंधित नीतियों, प्राथमिकताओं के अनुसार क्षेत्रीय विकास के लिए राज्य शासन को आवश्यक सुझाव दिया जाना है। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित किया जाना है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के 35 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में आधारभूत नागरिक सुविधाओं के कार्य, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के कार्य, शैक्षणिक सुविधाओं का विस्तार, स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का कार्य शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के अंतर्गत प्रमुख रूप से शिक्षा और छात्रावासों पर जोर दिया गया है।

बैठक में पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए चर्चा हुई। छात्रावासों का उन्नयन, प्रदेश में स्थित ओबीसी छात्रावासों के रख-रखाव और वहां सुविधाओं को बेहतर बनाने के निर्देश दिए गए। रोजगार और कौशल विकास पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि राज्य के पिछड़ा वर्ग के युवाओं को केवल सरकारी योजनाओं पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भर बनाया जाए। बैठक में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया गया। ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ ओबीसी आबादी अधिक है, वहां सड़कों, सामुदायिक भवनों और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए फंड आवंटित करने के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री का स्पष्ट संदेश दिया कि हमारी सरकार का लक्ष्य 'सबका साथ, सबका विकास' है। पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण की भूमिका केवल बजट आवंटित करने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। बैठक से यह स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार ओबीसी समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सक्रिय है और प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रही है। इस दौरान उप मुख्यमंत्री श्री अरूण साव, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्यामबिहारी जायसवाल, राजस्व मंत्री श्री टंकराम वर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, अनुसूचित जाति विकास, शिक्षा एवं तकनीकी मंत्री श्री गुरू खुशवंत साहेब, अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री ललित चन्द्राकर, स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव, सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायकगण, अन्य जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, श्री वासवराजू, शासन के विभिन्न विभागों के सचिव, आईजी, कमिश्नर, 17 जिलों के कलेक्टर एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995